

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

11 मार्च, 2002

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 11 मार्च, 2002

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(5)1
अध्यक्ष द्वारा घोशणा	(5)24
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(5)24
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये	(5)26

तारांकित प्र न एवं उत्तर	
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(5)31
भोक प्रस्ताव	(5)42
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	(5)43
पंजाब क्षेत्र में एस0वाई0एल0 कैनल को पूरा करने संबंधी	(5)43
वक्तव्य—	(5)44
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी मुख्यमंत्री द्वारा	(5)51
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	(5)51
चौधरी बंसी लाल द्वारा	(5)51
वयक्तव्य उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (पुनरारम्भ)	(5)51
वाकआउट्स	(5)57
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(5)60
वर्ष 2001—2002 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना	(5)71
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(5)71
अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(5)71

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 11 मार्च, 2002

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में मध्याह्न पचात् 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: ऑनरेबल मैम्बरज, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्र न संख्या 1004

(यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती सरिता नारायण सदन में उपस्थित नहीं थी)

Setting up of Fire Station, Kosli

***949. Smt. Anita Yadav:** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state-

whether there is any proposal under consideration of the Government to set up Fire Station at Sub-Tehsil, Kosli, District Rewari?

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्री सुभाश गोयल): जी, नहीं।

श्रीमती अनिता यादव: स्पीकर सर, कोसली सब डिवीजन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से और झज्जर डिस्ट्रिक्ट से 40-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर कोसली भाहर में आग लग जाती है तो जब तक इन भाहरों से फायर ब्रिगेड पहुंचता है तब तक तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना है कि क्या वे कोसली में फायर ब्रिगेड स्टे इन खोलने के लिए कोई प्रावधान करेंगे अगर करेंगे तो वह कब तक खोल दिया जायेगा?

श्री सुभाश गोयल: अध्यक्ष महोदय, कोसली भाहर में न तो नगरपालिका है न नगर परिशद है इसलिए नगरपालिका और नगरपरिशद न होने के कारण वहां पर फायर ब्रिगेड खोलने का सरकार का कोई विचार नहीं है। रेवाड़ी भाहर कोसली के नजदीक पड़ता है और रेवाड़ी में पहले ही फायर ब्रिगेड स्टे इन मौजूद है।

श्रीमती अनिता यादव: स्पीकर सर, रेवाड़ी भाहर कोसली से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है और जो कोसली से रेवाड़ी की सड़क है वह काफी टूटी हुई है जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में काफी देर लग जाती है। अब पिछले दिनों निगाण गांव में कड़बी में आग लग गई थी और जब तक फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची तब तक वह सारी कड़वी जल कर राख हो गई थी। इसी तरह कोसली में एक दुकान में आग लग गई थी और जब तक फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची तब तक वह सारी दुकान जल कर राख हो गई थी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से

अनुरोध है कि कोसली भाहर में फायर ब्रिगेड स्टे न खोलने का प्रावधान किया जाये। इसके साथ साथ में मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या जिन भाहरों की नगरपालिकायें भंग कर दी गई थी वहां के फायर ब्रिगेड हटाने का सरकार का विचार है, अगर नहीं तो फिर हमारे यहां कोसली में फायर ब्रिगेड स्टे न खोलने पर सरकार क्यों नहीं विचार कर रही है।

श्री सुभाश गोयल: स्पीकर महोदय, जिन नगरपालिकाओं की आबादी 15 हजार या 15 हजार से ज्यादा है वहां नगर पालिका एग्जिस्ट हो सकती है। ऐसी किसी नगर पालिका को भंग नहीं किया गया है और जिन नगरपालिकाओं को भंग किया गया है और वहां पर फायर ब्रिगेड स्टे न की सुविधा नहीं थी वहां पर यह सुविधा देने का कोई प्रावधान करने का सरकार का विचार नहीं है।

श्रीमती अनिता यादव: स्पीकर सर, मेरे प्र न का सही जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: आपके प्र न का जवाब आ गया है।

Opening of Mini Bank

***1010. Shri Ranbir Singh:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to open Mini Bank in Badhra Constituency?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना): नहीं, श्रीमान् जी, बाढ़ड़ा विधान सभा क्षेत्र में पहले ही 35 मिनी बैंक कार्यरत हैं।

श्री रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि बाढ़ड़ा क्षेत्र में 35 मिनी बैंक हैं लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 107 गांव हैं और इन में दो गांव काकड़ौली और पिचोपा कलां हैं वहां पर मिनी बैंक नहीं हैं। क्या मंत्री जी इन बड़े गांवों में मिनी बैंक खोलने का कष्ट करेंगे या भविष्य में सरकार की कोई ऐसी नीति है कि इन गांवों में मिनी बैंक खोलने पर विचार किया जा सके।

श्री करतार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि बाढ़ड़ा विधान सभा क्षेत्र में पहले ही 35 मिनी बैंक कार्यरत हैं और वहां के निवासियों की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई मांग हमारे पास नहीं आई है अगर ऐसी कोई मांग आई तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री रणबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के दो बड़े गांव काकड़ौली और पिचोपा कलां की पंचायतों ने इस बारे में लिख कर एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा हुआ है इस बारे में मैंने भी अपना सुझाव रखा था तो मैं माननीय मंत्री महोदय से

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वे इन गांवों में मिनी बैंक खोलने पर विचार करेंगे।

श्री करतार सिंह भड़ाना: अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव आया तो उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री रमे । कुमार खटक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मिनी बैंक खोलने के लिए क्या क्राईटेरिया है और क्या कंडी ंज हैं कृपा करके बतायें।

श्री करतार सिंह भड़ाना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि जिस गांव में 60 लाख रुपये तक कर्जा लेने वालों की संख्या हो वहां मिनी बैंक खोला जा सकता है।

श्री जसबीर सिंह मलौर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में भी मिनी बैंक की कमी है। पिछले दिनों आई0सी0डी0पी0 स्कीम के तहत जनसुई हैड पर एक्सटैं इन कांउटर खोला गया था लेकिन अभी तक उसको ब्रांच का दर्जा नहीं दिया गया है जिसकी वजह से 40 गांव प्रभावित हैं और उनको दूसरी भाखाओं में लेन देन के लिए जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री महोदय भी पिछले दिनों माजरी गांव में गए थे वहां उनके सामने इस बारे में मांग पत्र रखा गया था और उन्होंने वहां आ वासन दिया था कि इस ऐक्सटैं इन

कांउटर को ब्रांच का दर्जा दे दिया जाएगा लेकिन अभी तक उसको ब्रांच का दर्जा नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या उसकी ब्रांच का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री करतार सिंह भडाना: अभी इस पर विचार चल रहा है।

श्री भागि रंजन परमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मेरे हल्के मुंडाल में मालकोस मिनी बैंक खुला हुआ है लेकिन वह बैंक मालकोस की बजाय नीमडी में है। इससे दो तीन गांवों में डिस्प्यूट है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि यह बैंक जिस गांव के नाम से खोला गया है उसी गांव में खोला जाएगा इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह बैंक उसी गांव में होना चाहिए जिस गांव के नाम से खुला हुआ है या फिर उसका बायफरके तान कर दिया जाए इसके लिए केस आर0सी0एस0 आफिस में आया हुआ है और अगर ऐसा हो जाता है तो वहां के 2-3 गांवों का डिस्प्यूट सैटल हो जाएगा।

श्री करतार सिंह भडाना: अगर नार्म्स में कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री रामकुमार नगूरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि उचाना कलां में मुख्यमंत्री महोदय ने मिनी बैंक खोलने का आव वासन दिया था लेकिन अभी तक वह मिनी बैंक खोला नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उसमें कौन सी कार्यवाही बाकी रह गई है जिसकी वजह से यह मिनी बैंक खोला नहीं गया है।

श्री करतार सिंह भड़ाना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूँगा कि वे ये सवाल अलग से दें। फिलहाल जो प्र न पूछा गया है उसका जवाब दे दिया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ये जो मिनी बैंक सोसायटीज हैं क्या इनसे 50 रुपये से ज्यादा लोन लेने वाले किसानों के ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी लगाई हुई है?

श्री करतार सिंह भड़ाना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने सीनियर साथी को बताना चाहता हूँ कि वे इस बारे में अलग से नोटिस दे दें।

तारांकित प्र न संख्या—1008

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भीम सैन मेहता सदन में उपस्थित नहीं थे।

Strengthening of Power Distribution system

***966. Sh. Ramesh Rana:** Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to strengthen the Power Distribution System in Karnal Circle; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt., to set up new 33KV Sub-Station/augmentation 33 K.V. sub-station in Karnal Circle; if so, the details thereof?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा):

(क) हां श्रीमान्, करनाल परिमण्डल में पावर वितरण प्रणाली को 54 अत्याधिक ओवर लोडिड 11 के0वी0 फीडरों का पुर्न-स्थापना तथा द्वि-भाजन करके तथा अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों को जोड़कर नए उपकेन्द्रों का निर्माण तथा चालू उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करके सुदृढ़ किया जा रहा है। एक नया 33 के0वी0 उपकेन्द्र चालू किया गया है तथा 11 नं0 33 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमता पहले ही बढ़ाई जा चुकी है।

(ख) हां श्रीमान्, 17.30 करोड़ रुपए की लागत से सम्बन्धित लाईनों के साथ 11 नए 33 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण तथा 12 वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव है।

इन कार्यों को दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

(ए) करनाल सर्कल में निर्माण किए जा रहे 33 के०वी० उपकेन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:—

क्र० सं०	उपकेन्द्र का नाम	सर्कल का नाम	जिले का नाम	प्रस्तावित क्षमता (एमबीए में)	चालू होने का समय
1	2	3	4	5	6
1.	पाङ्डा	करनाल	करनाल	6.3	2002-03
2.	मंजूरा	करनाल	करनाल	6	2002-03
3.	जीटी रोड, पानीपत	करनाल	पानीपत	6	2002-03
4.	कुटानी रोड, पानीपत	करनाल	पानीपत (2 x 6.3)	12.6	2002-03
5.	सिवाह / दिवाना	करनाल	पानीपत	6.3	2002-03
6.	असंध रोड, पानीपत	करनाल	पानीपत (2 x 6.3)	12.6	2003-04

7.	बापोली	करनाल	पानीपत	6	2003-04
8.	डाहर	करनाल	पानीपत	6	2003-04
9.	निगधू	करनाल	करनाल	6	2003-04
10.	थल	करनाल	करनाल	6	2003-04
11.	सलवान	करनाल	करनाल	6	2003-04

(बी) करनाल सर्कल में निर्माण किए जा रहे 33 के0वी0 लाईनों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	33 के0वी0 लाईन का नाम	सर्कल का नाम	जिले का नाम (एमबीए में)	प्रस्तावित क्षमता	चालू होने का समय
1	2	3	4	5	6
1.	132के0वी0 उपकेन्द्र जुडला-पाड्डा लाईन	करनाल	करनाल	16	2002-03
2.	132के0वी0 उपकेन्द्र	करनाल	करनाल	7	2002-03

	जुडला-मंजूरा लाईन				
3.	132के0वी0 उपकेन्द्र चंदौली-जीटी रोड पानीपत लाईन	करनाल	पानीपत	6	2002-03
4.	टीऑफ चंदौली-सनोली रोड पानीपत लाईन 33 के0वी0 उपकेन्द्र कुटानी रोड, पानीपत के लिए	करनाल	पानीपत	0.2	2002-03
5.	400के0वी उपकेन्द्र सिवाह 33 के0वी0 उपकेन्द्र, सिवाह दीपाना लाईन	करनाल	पानीपत	4	2002-03
6.	टी-ऑफ गोहाना रोड	करनाल	पानीपत	0.5	2003-04

	पानीपत-मुनक लाईन असंध रोड, पानीपत के लिए				
7.	132के0वी0 उपकेन्द्र छाजपुर-बापोली लाईन	करनाल	पानीपत	10	2003-04
8.	132के0वी0 उपकेन्द्र मतलौडा प्रस्तावित डाहर लाईन	करनाल	पानीपत	12	2003-04
9.	132के0वी0 उपकेन्द्र सग्गा-निगधू लाईन	करनाल	करनाल	13	2003-04
10.	132के0वी0 उपकेन्द्र असंध-थल	करनाल	करनाल	12	2003-04

	लाईन				
11.	132के0वी0 उपकेन्द्र असंध-सलवान लाईन	करनाल	करनाल	11	2003-04
		योग		81.7	

(सी) जिला करनाल में 33 के0वी0 वर्तमान उपकेन्द्रों की वृद्धि किए जा रहे उपकेन्द्रों का विवरण :-

क्र0 सं0	उपकेन्द्र का नाम	सर्कल का नाम	जिले का नाम	क्षमता (एमबीए में)		अतिरिक्त क्षमता (एमबीए में)	चालू होन का समय
1	2	3	4	5	6		
				से	तक		
1.	बलाह	करनाल	करनाल	2x5	2x6.3	2.6	2002-0 3
2.	कोहांड	करनाल	करनाल	5+4	2x6.3	3.6	2002-0 3

3.	उपलाना	करनाल	करनाल	5+6. 3/8	6.3 + 6.3/8	1.3	2002-0 3
4.	काछवा	करनाल	करनाल	1x5	2X5	5	2002-0 3
5.	धमगढ़	करनाल	करनाल	5+4	2X5	1	2002-0 3
6.	तरावड़ी	करनाल	करनाल	5+6. 3/8	6.3 + 6.3/8	1.3	2002-0 3
7.	कुटैल	करनाल	करनाल	5+4	2x6.3	3.6	2002-0 3
8.	मेरठ रोड़	करनाल	करनाल	5+6. 3/8	6.3 + 6.3/8	1.3	2003-0 4
9.	डाचर	करनाल	करनाल	2X5	2x6.3	2.6	2003-0 4
10.	नगला मेघा	करनाल	करनाल	4+5+ 6.3	2x6.3+ 5	2.3	2003-0 4
11.	धीड़	करनाल	करनाल	2X5	2x6.3	2.6	2003-0 4

12.	बरसत	करनाल	करनाल	5+6. 3/8	6.3+6. 3/8	1.3	2003-0 4
	कुल-अतिरिक्त क्षमता (एमवीए)					28.5	2003-0 4

श्री रमे ा राणा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यह जो कार्य भुरू हो चुके हैं या भुरू होने वाले हैं वे कब तक पूरे हो जाएंगे?

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि इन कार्यों के पूरा होने का जो प्रोग्राम है उनके बारे में जवाब इस पटल पर रखी सूची में दिया गया है। अगर आप इजाजत दें तो मैं यह सूची पढ़ देता हूँ लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा क्योंकि यह बहुत लम्बी-चौड़ी सूची है। अध्यक्ष महोदय, वैसे इस सूची में लिखा हुआ है कि ये कार्य 2002-2003 और 2003-2004 तक पूरे हो जाएंगे। अगर सारा सदन जानना चाहेगा कि हमारी सरकार ने बिजली के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कितनी ज्यादा बिजली पैदा की और उसका वितरण बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये हैं जिसकी वजह से हरियाणा के किसानों का कृषि का उत्पादन बढ़ा और प्रदेश का नाम रोान हुआ तथा हमारे किसानों ने सेंट्रल

पूल में सबसे ज्यादा अन्न देने का काम किया। स्पीकर सर, यदि आप कहेंगे तो इसकी पूरी डिटेल्स मैं हाउस में पढ़कर सुना देता हूँ लेकिन इसमें काफी समय लग जायेगा।

श्री कृष्ण लाल: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० साहब से पूछना चाहूंगा कि जो सवाल मेरे साथी रामे 1 राणा ने पूछा है मेरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि जिला करनाल के अंदर 11 के०वी० और 33 के०वी० के कितने ट्रांसफार्मर्स पर लोड अधिक है और करनाल सर्कल के अंदर कहां-कहां पर 11 के०वी० और 33 के०वी० के सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जायेगी।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी कृष्णलाल जी को इस महकमें की बहुत नॉलेज है इसलिए इनकी संतुष्टि के लिए और पूरे सदन की संतुष्टि के लिए बताना चाहूंगा कि वर्तमान में 35 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है और चौधरी भजन लाल जी फिर कहेंगे कि मैंने इतना ज्यादा बता दिया क्योंकि काम ही इतना हुआ है जिसको बताने में समय तो लगेगा ही इसलिए मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि करनाल जिले में भादसां, एन०डी०आर०आई०, एच०एस०आई०डी०सी० उकलाना, डिकाडला, अजराना, खानपुर, कोलियां, गोदणी, मखाणा, ज्योतिसर, लूखी, चक्कू-लदाणा, चिक्का, खेड़ी गुलाम वाली, निसाद, बाढ़ला, मस्तगढ़, एच०एस०आई०डी०सी० पुण्डरी, खरखौदा, छाजपुर, अटेरना, लघु सचिवालय सोनीपत, फरमाना, बादली,

झज्जर, बपूनियां, अलेवा, बूढकलां, बाराखास रोड़ अम्बाला आदि सब स्टेांनों की क्षमता बढाई गई है।

श्री बलवंत सिंह: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माजरा साहब से पूछना चाहूंगा कि सढोरा के अंदर ट्रांसफार्मर पर लोड बहुत ज्यादा है, वहां पर 16 एम0वी0ए0 का एक ही ट्रांसफार्मर है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गये थे और उन्होंने वहां के लिए 16 एम0वी0ए0 का एक और ट्रांसफार्मर लगाने की घोशणा की थी वह कब तक लग जायेगा?

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी ने एक स्पैसीफिक प्र न पूछा है इसको हमने नोट कर लिया है इसको एग्जामिन करवा लेंगे यदि नार्मर्ज पूरे करता होगा और वास्तव में ही वहां लोड ज्यादा होगा तो एग्जामिन करवाने के बाद इसे टेकअप कर लिया जायेगा। स्पीकर सर, हमारा तो काम ही लोड म करने का है हम चाहते हैं कि किसान को और हमारे कन्ज्यूमर को अधिक से अधिक सुविधा हो।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि 17.30 करोड़ रुपये स्ट्रैंग्थनिंग ऑफ दी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर खर्च किए जा रहे हैं। इतना पैसा खर्च करने के बाद लाईन लौसिज कितने प्रति तात कम होंगे और अब लाईन लौसिज कितने प्रति तात हैं?

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, सब-स्टेानों की क्षमता इसलिए बढ़ाई जाती है कि फ्रिकवैन्सी तेज हो, लौसिज कम हो। कैप्टन साहब जो जानना चाहते हैं। ये उसका अलग से नोटिस दे दे हम उस बारे में इनको बता देंगे। स्पीकर सर, पूरे हरियाणा प्रदेश में सब स्टेान लगाये जायेंगे, अपग्रेड किए जायेंगे, लाईनों को बाईफ्रखेट करेंगे और उनका लोड कम करके लाईन लौसिज भी कम करेंगे। (विधन)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माजरा साहब ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न लाईन लौसिज से संबंधित नहीं है। (विधन)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठिये-बैठिये।

Strengthening of Distribution of Power

***917. Sh. Banta Ram Balamiki:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to strengthen the distribution system of Power in various Circle in the State, if so, the details thereof from the year 1999 to date?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): हां श्रीमान, राज्य के विभिन्न परिमण्डलों में विद्युत वितरण, प्रणाली को 11 के0वी0 भारी रूप से ओवर लोडेड बोझिल फीडरों को दो

भागों/तीन भागों में बांट कर तथा पुनः सक्षम करके, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर जोड़कर तथा 33 के0वी0 नये उपकेन्द्रों का निर्माण करके एवं 33 के0वी0 चालू उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि करके सुदृढ़ किया जा रहा है। 12 नये 33 के0वी0 उपकेन्द्रों तथा उनसे सम्बन्धित 211 किलो मिटर 33 के0वी0 लाइनें चालू की गई हैं तथा जुलाई 1999 से राज्य में 57 चालू 33 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है।

इन कार्यों का विस्तृत ब्यौरा द ार्ने वाला एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

राज्य में वितरण विद्युत प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जुलाई, 1999 से निम्न कार्य क्रियान्वित किए गए हैं—

1. 33 के0वी0 कार्य

(ए) नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र

क्र० सं०	उपकेन्द्र का नाम	जिले का नाम	क्षमता (एमवीए में)	चालू होने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	देवराला	भिवानी	1x6.3	30-7-1999
2.	चीका	कैथल	1x4	31-7-1999

3.	सिंघाना	जींद	1x4	5-1-2000
4.	जहाजगढ़	झज्जर	1x6.3	19-1-2001
5.	कवातरन	कैथल	1x4	23-3-2001
6.	आई०ए० सिरसा	सिरसा	1x4	27-5-2001
7.	सूर्या रोानी	झज्जर	1x6.3	28-6-2001
8.	बियाना	करनाल	1x6.3	30-7-2001
9.	गेन्दा	फतेहाबाद	1x4	31-8-2001
10.	खुटापुरा	रिवाड़ी	1x5	30-9-2001
11.	बावनिया	नारनौल	1x6.3	8-2-2002
12.	डबलाना	नारनौल	1x6.3	10-2-2002

बी०वी० 33 के०वी० उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि

क्र० सं०	उपकेन्द्रों के नाम	जिले का नाम	क्षमता (एम०वी०ए० में)	जोड़ी गई	पूर्ण होने
1	2	3	4	5	6
			से	तक	

1.	भादसो	करनाल	2x5	2x5+4	4	15-7-1999
2.	एन0डी0आर0आई रामनगर करनाल	करनाल	6.3/8.4	2x6.3/8	4	18-7-1999
3.	किरमीच	करनाल	5+4	5+6.3/8	4	18-5-2000
4.	मेरठ रोड करनाल	करनाल	2x5	5+6.3/8	3	20-5-2000
5.	तरावडी	करनाल	2x5	5+6.3/8	3	15-7-2000
6.	इसराना	पानीपत	2x5	3x5	5	15-7-1999
7.	जाम्बा	करनाल	5+6.3	6.3+6.3/8	3	19-8-2000
8.	सनौली रोडत्र पानीपत	पानीपत	5+6.3	2x6.3+5	6.3	1-11-2000
9.	कोहान्ड	पानीपत	1x4	4+5	5	7-11-2000
10.	उपलाना	पानीपत	1x6.3/8	6.3/8+4	4	24-1-2001

11.	डिकाडला	पानीपत	2x6.3	2x6.3+5	5	27-3-2001
12.	अजराना	कुरुक्षेत्र	2x6.3	2x6.3+4	4	15-7-1999
13.	खानपुर कोलियां	कुरुक्षेत्र	2x6.3	2x6.3+4	5	15-7-1999
14.	बोधनी	कुरुक्षेत्र	2x4 4+6.3	4+6.3 2x6.3	2.3 2.3	30-7-1999 6-10-2001
15.	मथाना	कुरुक्षेत्र	4+6.3/8	2x6.3/8		7-1-2000
16.	ज्योतिसर	कुरुक्षेत्र	3+4	2x4+6.3/8		15-5-2000
17.	लूखी	कुरुक्षेत्र	4+6.3	2x6.3		9-1-2001
18.	चाकुलदाना	कैथल	3x5	2x5+6.3		28-7-1999
19.	चीका	कैथल	2x4	5+4		17-8-1999
20.	खेड़ी गुलामअली	कैथल	2x4	4+6.3/8		7-3-2000
21.	इ ाक	कैथल	2x4	4+6.3/8	2.3	30-3-

			4+6.3/8	6.3+6.3/8		2000 20-7- 2001
22.	पाडला	कैथल	2x4+6.3	2x6.3+4	2.3	10-1- 2001
23.	मस्तगढ	कैथल	4+6.3	2x6.3	2.3	7-8- 2000
24.	एच0एस0आई0 डी0सी0 कुण्डली	सोनीपत	6.3+6.3 /8	2x6.3/8	1.7	16-7- 1999
25.	खरखोदा	सोनीपत	6.3+6.3 /8	2x6.3/8	1.7	21-7- 1999
26.	ताजपुर	सोनीपत	5+6.3/8	2x6.3/8	3	14-8- 1999
27.	अटेरना	सोनीपत	1x4	2x4	4	26-11- 1999
28.	लघु सचिवालय सोनीपत	सोनीपत	5+6.3/8	2x6.3/8	3	15-1- 2000
29.	फरमाना	सोनीपत	1x4	1x5	1	30-11- 2000
30.	बादली	झज्जर	1x5	1x6.3/8+4	3	3-11- 1999

31.	झज्जर	झज्जर	2+4	6.3+4	4.3	17-7-2001
32.	भूपनियां	झज्जर	1x4	1x6.3	2.3	3-8-2001
33.	अलेवा	जींद	1x4 1x6.3/8	6.3/8 1x6.3/8+4	4	3-11-1999 8-8-2001
34.	बुधकलां	यमुनानगर	1x4	2x4	4	16-1-2001
35.	12 क्रॉस रोड अम्बाला	अम्बाला	2x6.3	1x4	4	4-6-2001
36.	मुन्डिया खेडा	नारनौल	2x6.3 6.3+6.3/8	6.3+6.3/8 6.3+6.3/8	1.7 1.7	9-7-1999 18-7-1999
37.	भाड़ावास	नारनौल	1x4	1x6.3	2.3	22-11-2001
38.	पहलवास	नारनौल	1x2	1x4	2	26-11-2001
39.	कान्ती	नारनौल	1x2	1x5	3	30-1-2001

40.	बेहबलपुर	हिसार	1x4	1x6.3	2.3	15-7-1999
41.	विद्युत नगर हिसार	हिसार	1x5	1x6.3/8	3	29-5-2000
42.	एच0टी0एम0 हिसार	हिसार	1x4	1x6.3	2.3	24-2-2001
43.	अग्रोहा	हिसार	1x4	1x6.3	2.3	1-6-2001
44.	भट्टू	फतेहाबाद	1x2	1x4	2	23-7-2001
45.	रैनवाली	सिरसा	1x4	1x6.3	2.3	20-7-1999
46.	कालांवाली	सिरसा	1x4	1x5	1	26-7-1999
47.	गंगा	सिरसा	1x2 1x2	1x4 1x4	2 2	27-8-1999 9-11-2001
48.	पन्जुआना	सिरसा	1x4 1x5	1x6.3 1x6.3	2.3 1.3	14-10-1999 16-6-2001

49.	बहुदीन	सिरसा	1x5	1x6.3/8	3	10-8-2001
50.	कालांवाली	सिरसा	1x4	1x6.3	2.3	18-10-2000
51.	कादमा	भिवानी	1x2	1x5	3	15-10-1999
52.	लोहारू	भिवानी	1x4	1x6.3	2.3	28-10-1999
53.	इ ावाल	भिवानी		1x6.3 अतिरिक्त	6.3	8-1-2001
54.	सिवानी	भिवानी		1x4 अतिरिक्त	4	12-8-2000
55.	आई0ए0 भिवानी	भिवानी		1x4 अतिरिक्त	4	6-1-2001
56.	लोहारू	भिवानी	1x4	1x6.3	1.3	27-4-2001
57.	एस्कोट्स	फरीदाबाद	1x2	1x6.3	4.3	30-11-1999
	योग				193.7	

(सी) 33 के0वी0 लाइनें

राज्य में जुलाई 1999 से 211 कि० 33 के०वी० लाइन का निर्माण तथा चालू की गई है।

2.11 के०वी० कार्य

विभाजन/त्रिभाजन के बाद 60 नं० भारी बोझिल 11 के०वी० फीडर 157 नं० फीडर में तबदील कर दिए गए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य में जुलाई 1999 से निम्नलिखित कार्य पूर्ण किए गए हैं—

क्र०	विवरण	यूनिट	मात्रा
1	2	3	4
1.	11 के०वी० लाइनों का निर्माण	कि०मी०	2005 / यू०एच०बि०वि०एन०-1010, डी०एच०बि०वि०एन०-995
2.	एल०टी० लाइनों का निर्माण	कि०मी०	1651 डी०एच०बि०वि०एन०-675 डी०एच०बि०वि०एन०-996 /
3.	जोड़े गए वितरण ट्रान्सफार्मर	नं०	12204 / डी०एच०बि०वि०एन०-6145 डी०एच०बि०वि०एन०-6059 /

इन कार्यों के क्रियान्वयन के साथ ही विद्युत प्रणाली में बाधाएं/ब्रेक डाऊन घट गए हैं तथा प्रणाली की वि वसनीयता और विद्युत आपूर्ति की गणवत्ता में भी काफी हद तक सुधार हुआ है।

श्री बन्ता राम बाल्मीकि: स्पीकर साहब, मैं इस समाज के दयालु मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 2002-2003 में 33 के0वी0 के कितने सब स्टे ान लगाये जा रहे हैं?

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, मैं माननीय साथी श्री बन्ता राम जी को यह बताना चाहूंगा कि 2002-2003 के अन्दर 33 केवी के कितने नये उप केन्द्रों का निर्माण किया जायेगा। सर, 21 उपकेन्द्र तो उत्तरी विद्युत प्रसारण निगम तथा 11 उपकेन्द्र दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम बनायेगा। ये जो उप केन्द्र बनयो जायेंगे इनके नाम इस प्रकार हैं— पाढ़ा, करनाम में, मन्जुरा करनाल में, जी0टी0 रोड करनाल में, उटानी रोड पानीपत में, सिवाह पानीपत में, झांयसा कुरुक्षेत्र में, नैसी कुरुक्षेत्र में, मुरथली कुरुक्षेत्र में, जाखोली कैथल में, क्योड़क कैथल में, खेवड़ा सोनीपत में, केहरवाला सिरसा में, मंगाली हिसार में, रसूलपुर खेड़ी सिरसा में, खारिया सिरसा में, मेलाग्राम सिरसा में, उमड़ा हिसार में, सदनवास हिसार में, दरियापुर हिसार में, नारनोंद हिसार में इसके अतिरिक्त करनाल जिले के गांव राहड़ा में भी 33 के0वी0 का उप केन्द्र स्थापित करने का कार्य विचाराधीन है। स्पीकर

साहब, इसी प्रकार हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा भी 11 उप-केन्द्र बनाये जायेंगे।

श्री बन्ता राम बाल्मीकि: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें लाडवा, बबान और रादौर का कोई जिक्र नहीं है। हमारे यहां पर पैडी सीजन में बिजली की बड़ी भारी दिक्कत आती है। स्पीकर साहब, पड़ोस में भादी हो तो उसका हमें क्या फायदा। अर्थात् मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लाडवा, रादौर और बाबैन में बिजली की बड़ी भारी दिक्कत है। हमारा एरिया प्रदे 1 में सबसे ज्यादा अन्न देता है। हमारा एरिया गेहूं, जीरी और गन्ने की फसल भी दूसरे प्रदे 1ों से अधिक पैदा करता है। मंत्री जी ने भिवानी में या दूसरी जगहों पर नये उप-केन्द्र बनाने की बात बतायी है। इस बारे में मेरा कहना है कि उन एरियाज से अनुरोध करता हूं कि फसल देखने को भी नहीं होती। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करता हूं कि बाबैन, रादौर और लाडवा के अन्दर भी नये सब-स्टे 1न बनाने की तरफ ध्यान रखा जाता ताकि हम वहां पर धरती माता का सीना चीर कर और अधिक अन्न पैदा कर के समाज का भरण पोषण कर सकें।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकार साहब, कहीं पर भी सब-स्टे 1न बनाये जाने के लिए बाकायदा कुछ टर्म्ज एण्ड कन्डी 1ंज होती हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले प्लान में इनका काफी ख्याल रखा गया था। बन्ता राम

जी की यह बात सही है कि वहां पर और जगहों की अपेक्षा डिमांड भी ज्यादा है और वहां का एरिया भी फर्टाइल है और वहां के किसान भी मेहनती हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि वे वहां पर फिर भी किसी विशेष जगह पर ज्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो ये उसके लिए लिख कर भेज दें, उसको एगजामिन करवा लेंगे और वह स्थान नार्मर्ज पूरे करता होगा तो बन्ता राम जी की बात को पूरा अधिमान दिया जायेगा।

श्री धर्मवीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हम कई साल से सुन रहे हैं कि हम दो साल में इतनी बिजली पैदा करेंगे कि हमें बेचनी पड़ेगी। (विधन)

श्री अध्यक्ष: धर्मवीर जी, आप स्पीच न दें, केवल सप्लीमेन्टरी पूछें।

श्री धर्मवीर सिंह: सर, मैं सप्लीकेन्टरी ही पूछ रहा हूँ। स्पीकार साहब, बड़े दुःख की बात है कि भिवानी जिले में बिजली की दिक्कत का हमें सामना करना पड़ रहा है। (विधन) स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आज के दिन सतनाली से लेकर लोहारू, बहल, नक्कीपुर, तो गाम और जमालपुर के इलाके में कोई 33 के0वी0 का या 132 के0वी0 का नया सब-स्टेशन बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, अगर है तो वह कब तक चालू करेंगे। अब तक तो इनके दो साल

निकल गये और यदि काम न किया तो फिर आगे के भी 2-3 साल ऐसे ही निकल जायेंगे। (विधन)

श्री अध्यक्ष: आप कौन सी जगह चाहते हैं, वह जगह आप बताएं। आपने तो 6-7 जगह बता दी, आप कोई पार्टिकुलर जगह बताएं जहां पर आप सब-स्टे इन बनवाना चाहते हैं। (विधन)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे यह जानना चाहता हूँ कि ये किस जगह पर सब-स्टे इन चाहते हैं, यह तो बताएं।

श्री धर्मबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम ऑलरैडी बताएं हैं ये नाम नक्कीपुर, तो गाम, सतनाली, बहल, लोहारू, जमालपुर।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 100 किलोमीटर लम्बे एरिया का इकट्ठा मांग लिया और 100 किलोमीटर लम्बी लाईन की गिनती कर दी। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जहां पर इनका इन्ट्रस्ट है ये वहां की बताएं। वास्तव में इन्हें जहां किसान मिलते हैं और लोगों ने मांग की हो कि हमें सब-स्टे इन चाहिए, ये बताएं। अपनी मांगों को लेकर लोग इनके पास आए हों और कहा हो कि हम रिप्रैजैन्टे इन देते हैं आप इस पर विचार करें। अगर लोग इनसे मिले हों या कोई रिप्रैजैन्टे इन वगैरा इनको दी हो तो उस पर हम विचार कर सकते हैं लेकिन अगर यह सारी सौ किलोमीटर सड़क का कहे तो प्रॉब्लम है कोई

स्पेसिफिक सब-स्टे इन ये चाहते हैं तो बता दें हम उसे एग्जामिन करवा लेंगे। अगर वह नॉर्मर्ज, टर्मर्ज एण्ड कण्डी इन्ज को पूरा करता होगा तो इस पर जरूर गौर करेंगे।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में जहाजगढ़ का सब-स्टे इन है क्या यह पूरी कैपेसिटी पर चल रहा है और अगर यह पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रहा है तो क्या ये इसको एग्जामिन करवाएंगे कि यह कैपेसिटी पर चले, अगर हां तो यह कब तक पूरी कैपेसिटी पर चल पाएगा?

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, इनका प्र न क्लीयर नहीं हुआ इन्हें अपना प्र न क्लीयर करने के लिए कहने की मेहरबानी करें।

श्री अध्यक्ष: आप सब-स्टे इन का नाम तो बताएं?

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय मुख्य संसदीय सचिव महोदय जी से यह पूछना चाहता हूं कि जहाजगढ़ का सब-स्टे इन 166 कै०वी०ए० की प्रपोज्ड कैपेसिटी पर नहीं चल रहा है, यह कब तक अपनी पूरी कैपेसिटी पर चल पाएगा? (विध्न)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी यह बताएं कि क्या जहाजगढ़ का सब-स्टे इन वास्तव में ओवर लोडिड है?

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान: यह पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रहा है।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि जहाजगढ़ का सब-स्टे इन वास्तव में ओर लोडिड है, इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे अगर बाईफरकेट या ट्राईफरकेट लाईनें जाएंगी तो वह बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। इसके बारे में पूरा विवरण सदन के पटल पर जानकारी के लिए रखा है, यह इसमें देख लें।

श्री कृष्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य संसदीय सचिव महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने ऐसा कोई सर्वे करवाया है कि 11 के०वी०ए० 132 के०वी०ए० या 33 के०वी०ए० के सब-स्टे इन के अतिरिक्त वर्ष 2002-03 में नये पावर हाउस लगाने विचाराधीन हैं और मेरा दूसरा सवाल यह है कि सरकार आपके द्वार के तहत माननीय मुख्य मंत्र जी ने मेरे हल्के में 2 दरबार लगाए। सालवन गांव करनाल जिले का सबसे बड़ा गांव है वहा पर 33 के०वी०ए० के पावर हाउस की लोगों की डिमाण्ड थी और मुख्य मंत्री महोदय ने इसके लिए YES भी कहा है। मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने जो लिस्ट सदन के पटल पर रखी है उस लिस्ट में इस का नाम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य संसदीय सचिव महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस गांव को इस लिस्ट में भामिल करने बारे विचार करेंगे?

श्री रामपाल माजरा: जितने भी ओवर लोडिड सब-स्टे इन होते हैं उनका प्रोग्राम या नामों की डिमार्क इन पहले नहीं होती है, सबसे पहले उनकी जांच की जाती है और उनकी लिस्ट बनाई जाती है। अगले वर्ष के लिए 38 सब-स्टे इन्ज की जो सूची है उसमें पंवार साहब ने जो नाम बताया है वह गांव भामिल नहीं है लेकिन यह लिस्ट चेन्ज भी की जा सकती है, वह बदली भी जा सकती है। कहीं पर भी अगर ओवर लोडिंग हो जाए तो उस पर जांच की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं पंवार साहब को बताना चाहूंगा कि उन्होंने जिस बड़े गांव की चर्चा की है अगर वह नॉर्मर्ज पूरे करता होगा तो वर्ष 2002-03 के प्रोग्राम में उसका नाम नहीं है तो भी उसके नाम पर जरूर विचार करेंगे।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य संसदीय सचिव महोदय से जानकारी चाहूंगा। इन्होंने राज्य के विभिन्न सर्कलों में बिजली की वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव पटल पर रखा है उसमें डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में ऐस्कोर्ट के अतिरिक्त कोई नाम नहीं है। हथीन विधान सभा क्षेत्र में हथीन और औरंगाबाद के बारे में क्या सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और अगर है तो यह कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, जहां तक क्षमता बढ़ाने का प्र न है, 32 सब-स्टे इन्ज की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

अगर मैं इन सबके नाम बताने लग जाऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। यह एक तहर का प्रोग्राम है इसमें ऐसा नहीं है कि यह कांस्टीच्यूएन्सी-वाइज होगा या हथीन में अलग से होगा। यह क्षमता बढ़ाने के बारे में प्रोग्राम है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इस साल में 32 सब-स्टे ान्ज की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

तारांकित प्र न संख्या 914

(क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भाग सिंह जी सदन में उपस्थित नहीं थे यह प्र न पूछा नहीं गया)

Opening of National Law College at Gurgaon

***862. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether a National Law College has been opened at Gurgaon; if so, the details thereof?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह): हां, श्रीमान जी। महर्षि दयानन्द वि विद्यालय रोहतक द्वारा गुड़गांव में राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय खोला गया है। इस महाविद्यालय में अर्द्धवार्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के अन्तर्गत पांच वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि गुड़गांव में राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय में जो दाखिला होता है वह किस क्राईटेरिया के अनुसार होता है

और जब इस कालेज में दाखिला होता है तो उसमें अनुसूचित जातियों के बच्चों को ध्यान में रखा जाता है या नहीं रखा जाता है?

चौधरी बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय, महार्शि दयानन्द वि विद्यालय रोहतक द्वारा गुड़गांव में राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय खोला गया है जिसका उद्घाटन 7 अक्टूबर, 2001 को मुख्य मंत्री जी द्वारा किया गया था। अर्द्ध मासित पाठ्यक्रम प्रणाली के अन्तर्गत 5 वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम चलाने का लिए महाविद्यालय की स्थापना की गई है। महाविद्यालय में दाखिले अखिल भारतीय विद्या प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किए जाते हैं। अतः 50 फीसदी सीट्स हरियाणा प्रदेश के स्थाई निवासियों के लिए आरक्षित है। दाखिले के मामले में हरियाणा सरकार की आरक्षण नीति के कार्यक्रम का पालन पूर्णतः किया जाता है। हरियाणा सरकार के अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा भारतीय विधि परिषद के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय महाविद्यालय गुड़गांव सैक्टर-40 में एक सुन्दर भवन में स्थित है। महाविद्यालय का क्षेत्र लगभग 10 एकड़ तक का है। हरियाणा सरकार द्वारा बाहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से महाविद्यालय के लिए भूमि निःशुल्क प्रदान की गयी है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आरक्षण दिए जाने की बात है, जो आरक्षण नीति सरकार की है उसी के हिसाब से इस कालेज में भी आरक्षण दिया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह जो कालेज गुड़गांव में खोला गया है यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या मंत्री जी मुझे बताएंगे कि इस कालेज के एडमिशन एन0आर0आई0ज0 को और पेड सीट्स के लिए कोई प्रावधान रखा गया है, अगर रखा गया है तो कितना पैसा पेड सीट के लिए रखा गया है और कितने प्रतिशत सीट्स इनके लिए हैं। अगर इनके एडमिशन के लिए जो पैसा रखा गया है वह बहुत ज्यादा है तो क्या सरकार इसको कम करने के बारे में विचार करेगी?

चौधरी बहादुर सिंह: आप इस बारे में कोई स्पैसिफिक केस बता दें। वैसे हमारी सरकार की यह पॉलिसी है कि 50 प्रतिशत सीट्स हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए और 50 प्रतिशत बाहर के विद्यार्थियों के लिए है। अगर आपके पास फीस से रिलेटिड कोई स्पैसिफिक केस है तो आप उस बारे में सैप्रेटली लिखकर दे दें हम इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में खास करके जो मेवात का इलाका आता है, वहां पर बहुत ही पिछड़ापन है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद या रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे पिछड़े हुए या गांव के रहने वाले हैं क्या मंत्री जी बताएंगे कि उनके दाखिले के लिए कॉलेज में कोई रियायत देने का प्रावधान किया है।

चौधरी बहादुर सिंह: सरकार की पॉलिसी है कि एस0सीज0, बी0सीज0, एस0टीज0 और हैंडिकैप्ट्स के लिए ही आरक्षण नीति है। उसी के हिसाब से उस कॉलेज में आरक्षण दिया जा रहा है। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि एरियावाइज वहां पर कोई आरक्षण नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यह सवाल है कि गांवों में रहने वालों के जो बच्चे हैं खासकर मेवात के लोगों के, फरीदाबाद और अहीरवाल के गांवों के लोगों के बच्चे हैं जिनके बारे में मंत्री जी ने कहा कि इनके लिए कोई आरक्षण नहीं है। मैं मंत्री जी से दोबारा पूछना चाहूंगा कि क्या प्राथमिकता के आधार पर इन लोगों के बच्चों का उस महाविद्यालय में आरक्षण के आधार पर दाखिला हो सकेगा क्या ये इस बारे में विचार करेंगे या नहीं करेंगे?

चौधरी बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसमें इलाकावाइज कोई आरक्षण की नीति नहीं है। सरकार की जो आरक्षण की नीति चल रही है उसके मुताबिक ही आरक्षण वहां पर दिया जाता है। इसके अलावा वहां से ऐसी कोई डिमांड भी नहीं आयी है कि उनके बच्चों को वहां पर आरक्षण का लाभ देकर एडमिशन देना है। अध्यक्ष महोदय, केवल गुड़गांव में ही नहीं बल्कि रोहतक में भी या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी ये एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बारे में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: स्पीकर साहब, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन यह मेरे अपने क्षेत्र का मामला है बल्कि क्षेत्र का ही यह मामला है अपितु जहां यह कॉलेज स्थापित है वह मेरे अपने गांव की भूमि पर है। अभी मेरे एक मित्र ने वहां के क्षेत्र के गांवों के बच्चों के बारे में चिन्ता की। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उसने वहां के एक पिछड़े हुए गांव झाडसा की भूमि पर यह कॉलेज स्थापित किया। मैं अपने इन माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे एन0आर0आई0ज0 की चिन्ता न करें। मैं शिक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा कि जिस गांव के अंदर यह कॉलेज खुला है, वे उस गांव के आउस्टीज का इसमें एडमिशन के लिए ध्यान जरूर रखें। वे बताएं कि क्या इसमें एडमिशन के लिए वे उनको प्राथमिकता देंगे या नहीं देंगे।

चौधरी बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं डिप्टी स्पीकर साहब से गुजारिा करूंगा कि ये इस बारे में पहले पंचायत का प्रस्ताव भिजवाएं। इसके बाद ही सरकार इस बात को विचाराधीन कर लेगी। अगर हो सका तो वहां के बच्चों के लिए उस कॉलेज में रिजर्वेशन रखने की व्यवस्था जरूर की जाएगी।

श्री भागीराम: अध्यक्ष महोदय, इस महाविद्यालय के बारे में हमारे विपक्ष के लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। जो आज ये काली टोपी पहन कर हाउस में आये हैं, मंत्री जी बताएं कि इनके

लिए भी कोई वहां पर रिजर्वे न है या नहीं (हंसी) (गोर एवं व्यवधान)

श्री रामकि न फौजी: स्पीकर साहब, मैं गुजारी करूंगा कि इनको काली टोपी तो यमुनानगर के इलैक न में वहां के लोगों ने ही पहना दी थी इसलिए मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अब ये क्यों काली टोपी पहनकर आए हैं। (गोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब,

श्री जयप्रकाश: स्पीकर साहब, (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठ जाएं। ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। अब अगला सवाल होगा।

Rationalizing Teaching Staff

***878. Sh. Jasbir Singh Mallour:** Will the Minister of State for Education be pleased to state the details of steps taken or proposed to be taken by the Government to rationalize the Teaching Staff on the basis of enrolment of students in the State; if so, the details thereof?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह): श्रीमान जी, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

भौक्षिक अमले को युक्तिसंगत बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गये
अथवा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम

उच्चतर शिक्षा

सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पद भरने हेतु असंख्य कदम उठाए गए हैं। पहले वांछित स्थानों पर संस्वीकृत पदों तथा शिक्षकों की अधिकता थी जिसके कारण ग्रामीण महाविद्यालयों में पर्याप्त अमला नहीं था। भारी कमी वाले अर्द्ध भाहरी/ग्रामीण महाविद्यालय अमले की कमी की मार झेल रहे थे जबकि भाहरी महाविद्यालयों में अमला आवकता से अधिक था। संस्वीकृत पद महाविद्यालय में छात्र संख्या पर पूर्णतः आधारित नहीं थे। अतः सरकार द्वारा संस्वीकृत पदों तथा प्राध्यापकों की असंतुलित तैनाती ठीक करने के लिए विस्तृत युक्तिकरण आरम्भ किया गया। अब पूर्णतः छात्रों की संख्या के आधार पर अमले की तैनाती की गई है। युक्तीकरण के परिणामस्वरूप मुख्यतः ग्रामीण महाविद्यालयों में 250 प्राध्यापक स्थानान्तरित किए गए हैं। अमले की कमी को पूरा करने के लिए 269 नए भर्ती किए गए प्राध्यापक भी नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने नए भर्ती किए गए प्राध्यापकों को तीन वर्ष की अवधि तक ग्रामीण महाविद्यालयों में तैनात करने का नीतिगत निर्णय भी लिया है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालयों से आवक डेटा संग्रहीत किया गया है। दाखिल

छात्रों तथा तैनात शिक्षकों के सम्बन्ध में सूचना की डेटा एन्ट्री की जा रही है। उसके पश्चात् कार्य नॉर्म तथा छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की तैनाती को युक्तीसंगत बनाया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा

सरकार द्वारा राजकीय प्राथमिकता विद्यालयों में पहले ही युक्तीकरण किया जा चुका है तथा इसके परिणामस्वरूप 4626 पद फालतू हो गए हैं। फालतू अध्यापकों को उसी जिले में रिक्तियों के समक्ष समायोजित किया जा रहा है। बाकी फालतू अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर अन्य जिलों में समायोजित किया जाएगा।

श्री जसबीर मलौर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जो टीचिंग स्टाफ की रैनेलाइजेसन की पोलिसी लागू की गयी है उसका क्राईटेरिया क्या है? कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कितने टीचर लगाने की व्यवस्था की गयी है। मंत्री जी ने रिप्लाइ में नये अध्यापकों की भर्ती का भी जिक्र किया है, कि इन अध्यापकों को तीन वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाना जरूरी होगा। स्पीकर साहब, यह तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जैसा हमने अम्बाला में देखा है कि कई अध्यापक दस दस सालों से एक ही स्कूल में भाहरों में हैं और वे लॉग स्टे को तोड़ने से रोकने के लिए निचले स्तर पर मिलकर म्यूचुअल केस बनाकर डिपार्टमेंट को

भिजवा देते हैं जबकि कई अध्यापक ऐसे भी हैं जो दस-दस सालों से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में ही पढ़ा रहे हैं। क्या सरकार की कोई ऐसी पोलिसी है कि इस तरह के टीचर्स का ट्रांसफर किया जा सके।

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह): अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पद भरने हेतु असंख्य कदम उठाए गए हैं। पहले वांछित स्थानों पर संस्वीकृत पदों तथा शिक्षकों की अधिकता थी जिसके कारण ग्रामीण महाविद्यालयों में पर्याप्त अमला नहीं था। भारी कमी वाले अर्द्ध गहरी/ग्रामीण महाविद्यालय अमले की कमी की मार झेल रहे थे जबकि भाहरी महाविद्यालयों में अमला आव यकता से अधिक था। संस्वीकृत पदों तथा प्राध्यपकों की असंतुलित तैनाती ठीक करने के लिए विस्तृत युक्तिकरण आरंभ किया गया। अब छात्रों की संख्या के आधार पर अमले की तैनाती की गई है। युक्तिकरण के परिणामस्वरूप ग्रामीण महाविद्यालयों में 250 प्राध्यापक स्थानांतरित किए गए हैं। अमले की कमी को पूरा करने के लिए 269 नये भर्ती किए गए प्राध्यापक भी नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने नये भर्ती किए गए प्राध्यापकों को तीन वर्ष की अवधि तक ग्रामीण महाविद्यालयों में तैनात करने का निर्णय लिया है। जो 250 कॉलेज लैक्चरर भाहरों में बैठे थे उनको बाहर भेजकर उनकी जगह 269 नये भर्ती किए थे वे सारे के सारे रूरल एरियाज में लगाए गए हैं।

अब हमें सरकार से 152 पद भरने की अनुमति मिल चुकी है 152 पद हम कमी उन को भेज चुके हैं, 76 पद बकाया हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी ऐडवर्टाइजमेंट के लिए एच0पी0एस0सी0 को भेज दिया जाएगा।

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो अध्यापक भाहरों में सर्विस करते हैं उनको हाउस रेंट ज्यादा दिया जाता है और जो गांव में करते हैं उनको कम हाउस रेंट दिया जाता है जबकि उनका खर्च ज्यादा होता है, उनको ज्यादा मिलना चाहिए क्या सरकार इसमें कोई परिवर्तन करेगी?

चौधरी बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्रू को बताना चाहूंगा कि सरकार पॉलिसी बना रही है। जो शिक्षक भाहरों में काफी दिन से बैठे हैं उनको देहात में भेजेंगे और जो देहात में भुरू से सर्विस कर रहे हैं उनको ऐडजस्टमेंट करके भाहर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह रैनेलाइजे उन किया है या नहीं है कि एक आदमी जैसे अम्बाला कैंट में बैठा है तो वह वहीं के दूसरे स्कूल में चला गया, इस तरह की कोई नीति नहीं है। जो देहात और भाहर के हैं उनकी आपस में ऐडजस्ट करने की कोशिश करेंगे।

श्री जसबीर मलौर: अध्यक्ष महोदय, मेरा जो क्वैशन था उसका मैं उत्तर मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि

रे इनेलाइजे इन का क्या क्राइटेरिया है और कितने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर की जरूरत है और कितना स्टाफ सरप्लस हो गया है?

चौधरी बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारे राजकीय प्राथमिक स्कूलों में पहले ही युक्तीकरण किया जा चुका है इसके परिणामस्वरूप 4626 पद फालतू हो गए हैं, फालतू अध्यापकों को उसी जिले में रिक्तियों के समक्ष समायोजित किया जा रहा है। बाकी फालतू अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर अन्य जिलों में समायोजित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रो० राम भगत: अध्यक्ष महोदय, बड़े फख की बात है कि हरियाणा सरकार ने स्कूल और कॉलेजिज के अंदर स्टाफ की जो जरूरत थी रे इनेलाइजे इन के तहत और नयी भर्तियों से स्टाफ रे इनेलाइजे इन के तहत पूरा किया जा रहा है। मैं आपके से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतने स्टाफ के बावजूद जो पूरी सीटें हो चुकी है क्या कॉलेज और स्कूलज में जो क्लास टीचिंग है क्या उसकी सैंकिटटी को, उसके महत्व को बहाल किया गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी स्कूल हैं चाहे वे स्कूल भाहरों में हैं, खास तौर से ग्रामीण अंचलों में जो स्कूल हैं वहां क्लासिज में टीचर नहीं होते। बच्चे पढ़ाई के बगैर बैठे रहते हैं वहां पढ़ाई के बगैर बड़ा ही निरा राजनक वातावरण देखने को मिलता है इसलिए वहां छोटी-छोटी पढ़ाई की दुकाने भगुरु हो रही हैं और

उनमें ज्यादा बच्चे जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में बराबर हाजिरी गिरती जा रही है। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो टीचर सरकारी स्कूलों में 15-20 हजार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं क्या वे समाज के साथ, सरकार के साथ और बच्चों के साथ इंसॉफ कर रहे हैं? मैं जानना चाहूंगा कि इस बारे में हरियाणा सरकार व संबंधित शिक्षा विभाग क्या कोई कदम उठा रहे हैं?

चौधरी बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के विशय में यह काफी चिंता का मामला है हमारी सरकार जब से बनी है तब से आदरणीय चौटाला साहब के नेतृत्व में पूरी कोशिश है कि जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें प्रोसैस पूरी की जाए। हमारे स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे थे लेकिन जब से नयी शिक्षा नीति लागू की है तबसे काफी फर्क पड़ा है पहली कक्षा से अंग्रेजी भुरु की है तब से काफी फर्क पड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इन स्कूलों में हैडमास्टर नहीं है या बच्चे चाली बैठे हैं।

राव दान सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां तक रैनेलाइजेसन का सवाल है इसमें देखने को मिला है कि अधिकारियों के लैवल पर ऐसी गलतियां देखने को मिली हैं या सरकार ने की हैं वहां पर हकीकत में जरूरत के हिसाब से न करके पिक एण्ड चूज के हिसाब से ट्रांसफर किए गए हैं। एक स्कूल तो ऐसा है जहां एक सब्जैक्ट के लिए दो तीन टीचर्ज हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वे ऐसा कोई नियम बनाने जा रहे हैं कि कोई टीचर इस बात के लिए परे गान न हो कि उसके साथ कोई ज्यादाती हो रही है। सरकारी स्कूलों से परे गान होकर बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या सरकार इन पर कोई रोक लगा रही है और पिक एण्ड चूज की पोलिसी को खत्म कर रही है? क्योंकि टीचर तो चाहे भाहर का हो चाहे गांव का लेकिन इस का नुकसान तो बच्चे ही उठाते हैं।

चौधरी बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो रै गनेलाईजे गान स्कीम सरकार ने बनाई है उसमें यह प्रावधान रखा है कि जिस स्कूल में सरप्लस अध्यापक होंगे वहां से सीनियर अध्यापक को दूसरी नजदीक की जगह में बदला जायेगा इसमें पिक एण्ड चूज वाली कोई बात नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो उच्चतर, माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए रै गनेलाईजे गान की स्कीम बनाई है उनमें सैंक गंड पोस्टें कितनी हैं और उनके अगेंस्ट अपाईट कितने अध्यापक कर रखे हैं और जो अध्यापक गांवों में सर्विस करते हैं उनके लिए कोई रूरल अलाऊंस देने का प्रस्ताव क्या सरकार के विचाराधीन है जिससे भाहरों में ज्यादा सरप्लस स्टाफ न हो।

चौधरी बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो भाहरों में फालतू अध्यापक हैं रै। नेलाईजे। न स्कीम के तहत ऐसे फालतू अध्यापकों को गांवों में बदलने का सरकार का विचार है और जो गांवों में फालतू और कई सालों से अध्यापक बैठे हैं उनको नजदीक के भाहरों में बदलने का सरकार का विचार है।

श्री मांगेराम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि प्राइमरी अध्यापकों के 4626 पद फालतू हो गये हैं। जबकि सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाना प्राइमरी स्कूलों में कंपलसरी कर दिया है उस हिसाब से तो पोस्टें और बढ़ानी चाहिये थीं क्योंकि अंग्रेजी सब्जैक्ट और ऐड किया गया है जबकि मंत्री जी कह रहे हैं कि अध्यापक फालतू हो गये हैं।

चौधरी बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अलग से अध्यापक नहीं रखे हैं जो अध्यापक प्राइमरी की क्लासिज को पढ़ाते हैं वहीं इंग्लिश का विषय भी पढ़ायेंगे। हमने तो रै। नेलाईजे। न स्कीम के तहत जो अध्यापक कई सालों से एक ही स्थान पर बैठे हुये हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने की स्कीम बनाई है और उनको दूसरे नजदीक के स्थानों पर ऐडजस्ट करने जा रहे हैं।

श्रीमती अनीता यादव: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि एक तरफ तो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ मेरे विधानसभा क्षेत्र साल्हावास के कोसली सब डिवीजन में कई जगह ऐसी है जहां प्राइमरी स्कूल भी नहीं हैं जबकि कोसली सब डिवीजन में 36 बिरादरी रहती हैं। दूसरी तरफ हम एजुकेशन और टैक्नालाजी और कम्प्यूटर की बात करते हैं। क्या सरकार का कोसली सब-डिवीजन में प्राइमरी स्कूल खोलने का कोई प्रावधान है अगर नहीं तो क्यों नहीं?

चौधरी बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां प्राइमरी स्कूल न हो। (गौर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनीता यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि कोसली गांव 4000 आबादी वाला गांव है और अगर वहां कोई सरकारी प्राइमरी स्कूल हो तो मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगी। (गौर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान:

श्री अध्यक्ष: कादयान जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि इन्होंने प्राइमरी

स्कूलों से अंग्रेजी चालू करके लोगों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इससे स्कूलों में जो बच्चे कम हुए हैं उनके बारे में बताएं तथा जो टीचर्स सरप्लस हो गए हैं उनको ये रिट्रैंच करेंगे या उनको घर भेज देंगे इस बारे में भी बताएं।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो शिक्षा मंत्री जी ने डिटेल में जवाब दे दिया है। लेकिन सवाल रैनेलाइजेन का है। (गोर एवं व्यवधान) जवाब देने की रिसर्पोसिबलिटी अकेले पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर की नहीं बल्कि सरकार की कलैक्टिव रिसर्पोसिबलिटी होती है। अकेला पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ही नहीं कोई भी मिनिस्टर जवाब दे सकता है। इनको शिक्षा मंत्री जी ने डिटेल में पढ़कर सुनाया है और डिटेल में बताया है जहां तक कॉलेजिज में रैनेलाइजेन की बात है, तो जहां कहीं भाहर के कॉलेजिज में फालतू लैक्चरर हैं और कहीं गांव में लैक्चरर नहीं हैं तो उनको वहां भेजा गया है इस प्रकार कॉलेजिज में रैनेलाइजेन किया गया है और इसी तरह सैकेंडरी स्कूलों में रैनेलाइजेन प्रोसैस चल रहा है और प्राइमरी स्कूलों में रैनेलाइजेन प्रोसैस पूरा हो चुका है। जहां तक 4626 सरप्लस टीचर्स की बात है तो शिक्षा मंत्री जी ने इसका जवाब डिटेल में दे दिया है कि 4626 सरप्लस टीचर्स स्टेट में नहीं बल्कि स्कूलों के अन्दर सरप्लस है। जैसे किसी स्कूल में 6 टीचर्स हैं और वहां रिक्वायरमेंट 5 की

है तो वहां एक टीचर सरप्लस हो गया। ये 4626 सरप्लस टीचर्स विभिन्न स्कूलों में हैं इनके बारे में मंत्री जी ने पहले ही कहा है, चाहे तो ये रिकार्ड देख लें कि जो ये सरप्लस टीचर्स हैं इनको उसी जिले में ऐडजस्ट किया जाएगा और अगर उसी जिले में एडजस्ट नहीं हो सकेंगे तो इनको दूसरे जिले में एडजस्ट किया जाएगा। इसलिए सरप्लस का मतलब कोई छंटनी नहीं है बल्कि जहां टीचर्स की कमी है इनको वहां भेजा जाएगा। इनको तो इस बात के लिए एप्रींशियेट करना चाहिए था। रैस्ट ए योरड किसी की कोई छंटनी नहीं हो रही है। जहां काम होगा इन सरप्लस टीचर्स को वहीं भेजा जाएगा इनको खाली नहीं बैठने दिया जाएगा ताकि वे बच्चे पढ़ाएं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने समय में तो सुविधा के अनुसार कहीं एक टीचर बिठा रखा था और कहीं 10 टीचर्स बिठाए हुए थे। अब सुविधा नहीं चलेगी बल्कि काम के हिसाब से टीचर्स को लगाया जाएगा ताकि लोगों को फायदा मिल सके।

श्री मांगेराम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी ने ठीक जवाब दिया है और मैं इससे संतुष्ट हूँ। वित्त मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि ये सरप्लस टीचर्स इस बात से हैं कि कुछ स्कूलों में टीचर्स फालतू बैठे थे और कहीं टीचर्स कम बैठे थे, जिस डिस्ट्रिक्ट में जरूरत होगी उनको वहां डैपुटे इन पर भेजा जाएगा यह ठीक है। (गोर एवं व्यवधान) इन सरप्लस टीचर्स को डैपुटे इन पर ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट

में भेजना पड़ेगा। (गोर एवं व्यवधान) इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब आलरेडी आन रिकार्ड आप कह रहे हैं कि 4626 टीचर्स सरप्लस हैं और उनका रैग्नेलाइजेशन किया जा रहा है तो पिछले दिनों जो 5000 जे0बी0टी0 टीचर्स की भर्ती की गई है वह किस परपज से की गई है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कॉलेज से लेकर स्कूल तक की पॉलिसी के बारे में दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे किसी कॉलेज में कॉमर्स लैक्चरर की एक पोस्ट सैकशन है। और वहां पर स्टूडेंट एक भी नहीं है और किसी दूसरे कॉलेज में 40 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से जिस कॉलेज में स्टूडेंट नहीं हैं वहां पोस्ट सरप्लस हो गई इसलिए वहां स्टूडेंट हैं हम लैक्चरर को वहीं भेजेंगे। इसी तरह से प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के बारे में जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने अपनी रिप्लाइ में बताया है कि Surplus teachers are being adjusted against vacancies in the same District. Remaining surplus teachers shall be adjusted in other districts on deputation. इस तरह से प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ऐडजस्ट किया जायेगा। जहां पर 5000 टीचर्स नये भर्ती किए हैं। उनकी बात है वे खाली पोस्टों की जगह भर्ती किए गए हैं उस समय रैग्नेलाइजेशन नहीं हुआ था। इन पोस्टों को भरने के बाद टीचर्स को वहीं भेजा जा रहा है जहां बच्चे अधिक हैं। स्पीकर सर, हम किसी को मुफ्त में तनख्वाह नहीं देंगे, किसी को सूविधा के अनुसार पोस्टिड नहीं करेंगे। जहां बच्चसे होंगे वहीं

पर टीचर्ज को भेजा जायेगा। स्पीकर सर, कांग्रेस की सरकार के समय में तो एस0डी0ओ0, डी0ओ0, और बी0ई0ओ0 के आफिसों में ही 10-10 टीचर रहते थे और मुफ्त में तनख्वाह लेते थे। लेकिन हम टीचर्ज को खाली नहीं बैठायेंगे ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके। स्पीकर सर, जहां तक अंग्रेजी का सवाल है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बाकायदा टीचर्ज को ट्रेनिंग दी गई है, रिफ्रैशर कोर्स दिया गया है। इन अच्छे कामों के लिए मांगे राम गुप्ता जी को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए लेकिन ये अपनी बात ही किए जा रहे हैं। (तोर एवं व्यवधान)

घोशणा

अध्यक्ष द्वारा

श्री अध्यक्ष: जो सदस्य हाउस में मोबाईल फोन लेकर बैठे हैं वे मोबाईल फोन को या तो हाउस से बाहर रख दें या उसका स्विच ऑफ कर दें। इसके अलावा मैं सभी माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे नव निर्वाचित विधायक श्री मलिक चंद गंभीर जी ने आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था नीचे लायब्रेरी के साथ की है इसमें आप सभी आमंत्रित हैं, प्रैस के साथी भी आमंत्रित हैं और सभी अधिकारीगण भी आमंत्रित हैं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Amount Sanctione by H.R.D.F. in Mewat area

***969. Sh. Nafe Singh Rathee:** Will th Chief Minister be pleased to State the constituencywise total amount sanctioned by H.R.D.F. in the various constituencies of Mewat Area like Taurau, Nah and Ferozepur Jhirka during the period from 11-5-1996 to 24-7-1999 togetherwith the amount sanctioned in the above said constituencies during the period from 25-7-1999 to 31-1-2002?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा):
एच0आर0डी0एफ0 स्कीम के तहत ग्रामीण विकास कार्यों के लिए मेवात के निर्वाचन क्षेत्रों में जैसे तावडू, नूंह तथा फिरोजपुर झिरका में 11-5-1996 से 24-7-1999 तक एवं 25-7-1999 से 31-1-2002 तक की अवधि के दौरान निम्न प्रकार से राशि स्वीकृत की गई है:-

निर्वाचन क्षेत्र	11-5-1996 से 24-7-1999 तक स्वीकृत राशि	25-7-1999 से 31-1-2002 तक स्वीकृत राशि
तावडू	218.68	1022.85
नूंह	87.58	855.60
फिरोजपुर झिरका	124.09	694.99
कुल जोड़	430.35	2573.44

चौधरी नफे सिंह राठी: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूंगा कि 1991 से 1996 तक चौधरी भजन लाल जी की सरकार के समय में इन क्षेत्रों के लिए कितनी राशि एच०आर०डी०एफ० के तहत दी गई।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, इस बारे में मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि भजन लाल जी की सरकार के समय में सारा पैसा आदमपुर में ही लगता था किसी दूसरी जगह नहीं लगता था लेकिन मेरे साथी अलग से इस बारे में लिखकर मुझे दे दें, इनको पूरी जानकारी दे दी जायेगी।

श्री कृष्णपाल: स्पीकर साहब, अभी सी०पी०एस० साहब ने तावडू, नूंह और फिरोजपुर झिरका क्षेत्रों का आंकड़े बार ब्यौरा दिया है कि एच०आर०डी०एफ० के माध्यम से वहां पर कितना-कितना पैसा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये हरियाणा प्रदेश के दूसरे विधान सभा क्षेत्रों का ब्यौरा भी आंकड़े बार बताएंगे कि एच०आर०डी०एफ० से विधान सभा क्षेत्र वाईज कितना-कितना पैसा अलाट किया गया है। यदि यह पैसा अलाट किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, यह ठीक है कि मैंने 3 विधान सभा क्षेत्रों का आंकड़े बार ब्यौरा दिया है। इस बारे में मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि सभी 90 के 90

विधान सभा क्षेत्रों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जा-जा कर यह पूछा गया है कि तुम्हारे गांव में क्या तकलीफ है, क्या आपके यहां पर गलियां कच्ची हैं, क्या आपके यहां पर हरिजन चौपाल, बैकवर्ड चौपाल और जनरल चौपाल हैं या नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी कृष्णपाल जी ने बहुत लम्बी चौड़ी डिटेल्स पूछ ली हैं। आज हमारा प्रदेश वास्तव में खुलाहाली का प्रतीक है। हर तरफ से आज खुलाहाली ही खुलाहाली नजर आ रही है और पूरे प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं। जो आंकड़े कृष्णपाल जी ने पूछे हैं उनके बारे में बताते हुए मैं सबसे पहले विपक्ष के नेता चौधरी भजन लाल जी के हल्के से भुंरु करता हूँ। इनके क्षेत्र में वैसे तो पहले ही काफी काम हो चुके हैं लेकिन चौटाला साहब बड़े मेहरबान थे इसलिए इन्होंने सोच लिया कि वहां पर कोई कसर रह गई हो तो उसको ध्यान में रखते हुए आदमपुर में इस स्कीम के तहत 1 करोड़ 61 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं जो कि अपने आप में एक मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला सिटी में 78 लाख 74 हजार मंजूर किए गए हैं। असंध के अन्दर जिसके बारे में मेरे साथी ने सभी विधान सभा क्षेत्रों का ब्यौरा मांगा है यानि कृष्णपाल जी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर यानि असंध के अन्दर 2 करोड़ 84 लाख 37 हजार रुपये मंजूर हुए हैं। इसी प्रकार से अटेली हल्के में जहां का प्रतिनिधित्व भाई नरेन्द्र सिंह जी करते हैं, उनके हल्के में 4 करोड़ 80 लाख 66 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। (विधन) चौटाला साहब ने इस बात की

परवाह नहीं की कि वहां का प्रतिनिधित्व विपक्ष के भाई राव नरेन्द्र सिंह जी करते हैं।

श्री अध्यक्ष: नरेन्द्र सिंह जी, अब खुद तो हैं ना।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, बाढडा में 8 करोड़ 2 लाख 92 हजार रुपये मन्जूर किए हैं जिनमें से 6 करोड़ 95 लाख 30 हजार रुपये रिलीज भी हो चुके हैं। (विधन)

चौधरी भजन लाल: इसमें आप क्या कर रहे हैं, यह तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया का पैसा है।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल जी कह रहे हैं कि यह स्कीम तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया की है। ये प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं इन्हें अभी तक हरियाणा रूरल डिवैल्पमेंट फण्ड का पता नहीं है। इनको यह नहीं पता कि रूरल डिवैल्पमेंट फण्ड क्या होता है। इनको यह नहीं पता कि सैन्टर की कौन सी स्कीमें हैं और हरियाणा सरकार की कौन सी स्कीमें हैं। स्पीकर साहब, मैं हरियाणा रूरल डिवैल्पमेंट फण्ड का जवाब दे रहा हूँ। 85 लाख 58 हजार रुपये मन्जूर हुए हैं। बल्लभगढ़ में 2 करोड़ 9 लाख 97 हजार रुपये मन्जूर किए गए हैं। (विधन) बरवाला में 2 करोड़ 69 लाख 38 हजार रुपये मन्जूर किए गए हैं। (विधन) स्पीकर साहब, वे हां भी भर रहे हैं। काली टोपी वाले जय प्रकाश जी जो सबसे ज्यादा भाोर मचा रहे हैं वे हां भर रहे हैं। (विधन)

चौ० जय प्रकाश : स्पीकर साहब, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। (विधन)

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश जी, आप बैठ जाए।

चौ० जय प्रकाश : सर, ये गलत कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश जी, आप बैठ जाये। (गोर एवं विधन) जय प्रकाश जी की कोई बात रिकोर्ड न की जाये। सी०पी०एस० साहब, आप अपना रिप्लाइ कम्पलीट करें।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, बावल में 3 करोड़ 36 लाख 98 हजार रुपये मन्जूर हो चुके हैं। इसके अलावा बेरी में 1 करोड़ 90 लाख 99 हजार रुपये मन्जूर हुए हैं। (विधन)

चौ० जय प्रकाश : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आपको बोलने का अभी मैंने कोई अधिकार नहीं दिया है।

श्री रामपाल माजरा: भड्कलां का 97 लाख 98 हजार है (गोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, ये लोग अपने हल्कों का विकास देख कर राजी नहीं हैं। इनकी बात हम बताते हैं। (गोर एवं व्यवधान) हमने इनके क्षेत्रों में इतना विकास किया, इतना पैसा दिया ये लोग इस पर भी खुश नहीं हैं। इनको तो चाहिए था कि

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का धन्यवाद करते। (गौर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, ये लोग कहते हैं। (गौर एवं व्यवधान)

12.00 बजे

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Loss suffered by Haryana Roadways

***983. Shri Suraj Mal:** Will Transport Minister be pleased to state whether the Haryana Roadways suffered any loss during the last three years; if so, the reasons thereof together with the steps taken or proposed to be taken to make it viable?

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार): इस बारे में विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

हरियाणा राज्य परिवहन का पिछले तीन वर्षों में हानि का अस्थाई ब्यौरा निम्नलिखित है:—

क्र०सं०	वर्ष	हानि (करोड़ रुपये में)
1.	1998—99	89.64
2.	1999—2000	100.40 (अस्थाई)

3.	2000-2001	72.21 (अस्थाई)
4.	2001-2002	45.34 (अस्थाई)
(अप्रैल, 2001 से जनवरी 2002 तक)		

हानि के महत्वपूर्ण कारण:

1. हरियाणा में यात्रीकर की दर दे गभर में सबसे अधिक है। हरियाणा राज्य परिवहन में कर से पूर्व लाभ दे गभर की अन्य सभी राज्य परिवहन संस्थाओं से अधिक है।

2. वर्ष 1998-99 व 1999-2000 के दौरान अपर्याप्त मात्रा में बसों को बदला गया।

3. पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 01-1-98 से लागू करने तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्तों की किस्तों की अदायगी से स्थापना खर्चों में भारी बढ़ौतरी।

4. डीजल व लुब्रीकेंट सहित विभिन्न मदों की कीमतों में बढ़ौतरी।

5. विभिन्न श्रेणियों के लोगों को मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधायें प्रदान करने से हरियाणा राज्य परिवहन पर अत्यधिक भार-जैसाकि विद्यार्थी, कुछ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, स्वतन्त्रता सेनानी, विकलांग व्यक्ति, खिलाड़ी, लेखक और मान्यता प्राप्त संवाददाता इत्यादि।

6. सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु अल्प आय वाले मार्गों का संचालन।

7. परिचालन कार्य कुशलता में कमियां जिन्हें काफी हद तक ठीक किया जा चुका है तथा यह प्रक्रिया आगे जारी है।

हानि को कम करने हेतु उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम:

1. हरियाणा राज्य परिवहन की पुरानी बसों को बदलने व बसों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। लगभग 1200 पुरानी बसों को पहले ही पिछले दो वर्षों में बदला जा चुका है तथा 31 मार्च 2003 तक और 800 पुरानी बसों को बदलने की योजना है।

2. नई बसों की बाडी का डिजाइन आधुनिक, सुरक्षित तथा आरामदायक बनाया गया है। बसों के इस नये डिजाइन को आम जनता द्वारा काफी पसन्द किया जा रहा है।

3. परिचालन कार्यकुशलता में काफी सुधार लाया गया है जिसके परिणामस्वरूप बेड़े की उपयोगिता, वाहन उपयोगिता व बसों में यात्रियों की संख्या की वृद्धि से यातायात आय में काफी सुधार हुआ है। यह परिणाम विभिन्न कदम उठाने से प्राप्त हुये हैं जैसे कि मार्गों व समय सारणी को युक्तिसंगत बनाना, कम आय वाले अन्तर्राज्यीय मार्गों में कमी करना, राज्य के अन्दर महत्वपूर्ण मार्गों पर भाटल बस सेवायें शुरू करना, राज्य के सभी मुख्य बस

स्टैण्डों पर केन्द्रीय अग्रिम बुकिंग प्रणाली लागू करना, कई वित्तीय सुधारों को लागू करना, डिपुओं व उप-डिपुओं को तर्कसंगत बनाना, राज्य परिवहन के अमले की संख्या को युक्तिसंगत बनाया गया है जिसके परिणामस्वरूप राज्य परिवहन के कुल अमले की संख्या में काफी कमी आई है यह संख्या 31 मार्च, 1998 में 20985 से घटकर इस वर्ष 31 जनवरी 2002 तक 18960 रह गयी।

4. कर्मचारियों के वेतन इत्यादि तथा अन्य मदों की कीमतों में भारी बढ़ौतरी के बावजूद खर्चों पर काफी नियन्त्रण रखा गया है, जिसके कारण हानि में काफी कमी आई है।

5. कर्मचारियों को उत्साहित करने की तरफ काफी ध्यान दिया गया है जोकि हरियाणा राज्य परिवहन की दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी से साफ दिखाई देता है। इससे राज्य परिवहन के घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। हरियाणा राज्य परिवहन की कार्यकुशलता में सुधार को देखते हुये सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन के सभी पात्र कर्मचारियों को वर्ष 1998-99 का बोनस तथा वर्ष 1999-2000 व 2000-01 के लिये राज्य परिवहन के सभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अनुग्रह राशि देने की घोशणा की है।

Allocation of Foodgrains free of cost

***945. Sh. Ram Phal Kundu:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Central Govt. have allocated foodgrains free of cost under Sampooran Grameen Rozgar

Yojana (Food for work) to Haryana State during the year 2001-2002; if so, the district-wise details thereof?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा राज्य को वर्ष 2001-2002 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (काम के लिए अनाज) के अन्तर्गत 70818 मिट्टिक टन खाद्यान्नों का मुफ्त आबटन किया है। स्कीम के अन्तर्गत खाद्यान्न का जिलावार ब्यौरा विवरणी जा कि सदन की मेज पर रखी जाती है, में दिया गया है।

क्र०	जिले का नाम	2001-2002 के दौरान एस०जी०आर०वाई० के अन्तर्गत आबंटित कुल खाद्यान्न (मिट्टिक टन में)
1.	अम्बाला	3062
2.	भिवानी	4999
3.	फरीदाबाद	5110
4.	फतेहाबाद	3154
5.	गुड़गांव	5909
6.	हिसार	3975
7.	झज्जर	4198

8.	जीन्द	4259
9.	कैथल	3194
10.	करनाल	3417
11.	कुरुक्षेत्र	2214
12.	महेन्द्रगढ़	2942
13.	पंचकूला	2251
14.	पानीपत	2789
15.	रिवाड़ी	3080
16.	रोहतक	4703
17.	सिरसा	4134
18.	सोनीपत	3992
19.	यमुनानगर	3436
	कुल	70818

Laying of Sewarage System in Mahendergarh

***984. Rao Dan Singh: Will the Chief Minister be pleased to state:-**

Whether there is any proposal under consideration of the Govt. to lay sewerage system in Mahendergarh City; if so, the time it is likely to be laid down?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): नहीं, श्रीमान जी।

Krishak Uphaar Yojana

***988. Sh. Bhagwan Sahai Rawat:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the HSAMB is implementing a scheme namely 'Krishak Uphaar Yojana', if so, the details thereof?

कृषि मन्त्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू): हाँ, श्रीमान जी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने राज्य की सभी मण्डियों में 'कृषक उपहार योजना' 2 अक्टूबर, 2000 से प्रारम्भ की है।

इस परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में वर्ष में दो बार ईनामी ड्रा आयोजित किये जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में हर छः महीने में पुरस्कार कृषि उपकरणों के रूप में वितरण किये जा रहे हैं जिनकी राशि निम्न प्रकार है:—

प्रथम पुरस्कार	2	रुपये 40,000 /— प्रति पुरस्कार
द्वितीय पुरस्कार	8	रुपये 25,000 /— प्रति पुरस्कार
तृतीय पुरस्कार	12	रुपये 10,000 /— प्रति पुरस्कार

Setting up of Rice Mill At Rania

***996. Smt. Vidya Baniwal:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Rice Mill by HAFED at Rania; and

(b) if so, the time by which the above said Mill is likely to be set up?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भडाना):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) हैफेड द्वारा रानिया में आगामी धान सीजन से पहले ही चावल मिल स्थापित कर दी जाएगी।

Posts of Lecturers lying vacant

***895. Shri Nafe Singh Jundla:** Will the Minister of State for Education be pleased to state the number of posts of lecturers, if any lying vacant in Government College in the State at present; if so, the steps taken or proposal to be taken to fill up the said posts particularly in the College of rural areas?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह): श्रीमान जी, सम्बद्ध सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

राजकीय महाविद्यालयों में भौक्षिक अमले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में 269

प्राध्यापक नियुक्त किए गये हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की भी गणना की जाए तो 152 अतिरिक्त महाविद्यालय प्राध्यापकों की आव यकता होने की सम्भावना है जिसके लिए प्रथम चरण में पहले ही हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। विशयवार आव यकता का पता लगाने के लिए महाविद्यालयों के कार्यभार का पुनः आकलन किया जा रहा है तथा उसके बाद बकाया 76 पदों हेतु मांग आव यकतानुसार भेजी जायेगी।

ग्रीमाण क्षेत्रों के राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यपकों की आव यकता पूरी की जा चुकी है। ऐसा पहले भाहरी महाविद्यालयों में अधिक संख्या में तैनात शिक्षकों की युक्तिसंगत तैनाती करके किया गया है। इसके अतिरिक्त नये भर्ती किए गये प्राध्यापकों के द्वारा प्रथम तीन वर्ष की अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवा करने की नीति भी सरकार ने बनाई और लागू की है।

Augmentation of Drinking Water Projects

***967. Sh. Ram Kumar Saini:** Will the Chief Minister be pleased to state the number of villages districtwise, to be benefitted under the augmentation of drinking water projects in the State sanctioned by the NABARD?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): श्रीमान जी, इस बारे में सूची सदन के पटल पर रखी गई है।

क्रम सं०	जिला का नाम	लाभान्वित गांवों की संख्या
1.	सिरसा	45
2.	रोहतक	14
3.	झज्जर	47
4.	कुरुक्षेत्र	97
5.	भिवानी	59
6.	जींद	32
7.	महेन्द्रगढ़	14
8.	रिवाड़ी	10
9.	गुड़गांव	31
10.	पानीपत	34
11.	सोनीपत	33
12.	कैथल	26
13.	अम्बाला	77
	कुल	519

Completion of Lohari, Pataudi and Mujjfra Minors

***963. Sh. Ram Bir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state:-**

(a) the time by which the construction work of Pataudi minor, Lohari minor and Mujjfra minor in the Pataudi constituency will be completed; and

(b) the time by which the water will be released in the above said minor?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) इन योजनाओं की 31-3-2003 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(ख) माइनरों के पूरा होने के पश्चात् तुरन्त पानी छोड़ दिया जाएगा।

Setting up of City Police Station in Jhajjar

***1001. Sh. Daryao Singh: Will the Chief Minister be pleased to state-**

(a) whether there is any proposal under consideration of the government to set up City Police Station in Jhajjar.

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) —

Trauma Center

***976. Shr. Shadi Lal Batra:** Will the Minister of State for Health be pleased to state-whether the Govt. intends to start Trauma Center in the only state owned Medical College, Rohtak whose building has been constructed & completed?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (डॉ० मुनी लाल रंगा):
जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Declaration of Ambala Saha Road as National Highway

71. Sh. Anil Vij: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to get Ambala-Saha State Highway to be declared as National Highway.

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to strengthen and widen the Ambala-Jagadhan State Highway; and

(c) if so, the time by which the aforesaid proposal are likely to be materialized?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

(ग) राष्ट्रीय उच्चमार्ग घोषित करने के बारे में निर्णय भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाना है। अतः अम्बाला-साहा सड़क को कब तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित किया जाएगा बताया नहीं जा सकता।

Setting up of 220 KV Sub-Station, Tepla

72. Sh. Anil Vij: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a 220 KVA Sub-station is being set up at Tepla, Distt. Ambala;

(b) if so, the time by which above project is likely to be got completed; and

(c) the amount to be spent on it and the time by which Ambala Cantt. will start getting electricity supply from this sub-station?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) तेपला जिला अम्बाला में एक नया 220 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य पहले ही प्रगति पर है।

(ख) यह उपकेन्द्र वर्ष 2002-03 तक पूरा होना संभावित है।

(ग) इस उपकेन्द्र की अनुमानित लागत 18.66 करोड़ रुपए है तथा इससे सम्बन्धित 220 के०वी० डी/सी अब्दुल्लापुर तेपला लाईन की लागत 6.42 करोड़ रुपए है। वर्ष 2002-03 में इस उपकेन्द्र के चालू होने के बाद अम्बाला कैंट इस उपकेन्द्र से तत्काल बिजली आपूर्ति प्राप्त करना भुरू कर देगा।

Repair/Strengthening of Urban Roads

73. Sh. Anil Vij: Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair/strengthen the urban roads in the State; and

(b) if so, the amount sanctioned for each district during last five years?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल):

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) गत 5 वर्षों के दौरान सड़कों की मरम्मत/मजबूत बनाने के लिए राशि निम्न अनुसार स्वीकृत की गई:-

क्र०सं०	जिले का नाम	सड़कों की मरम्मत/मजबूत करने के लिए स्वीकृत की गई राशि (लाखों)
---------	-------------	---

		में)
1.	हिसार	400.93
2.	भिवानी	708.22
3.	सिरसा	267.91
4.	फतेहाबाद	203.85
5.	करनाल	649.13
6.	कैथल	291.53
7.	पानीपत	412.93
8.	जीन्द	208.49
9.	रोहतक	558.75
10.	झज्जर	507.35
11.	सोनीपत	495.10
12.	पंचकूला	164.13
13.	यमुनानगर	616.80
14.	कुरुक्षेत्र	689.09

15.	अम्बाला	723.02
16.	गुड़गांव	776.47
17.	फरीदाबाद	266.22
18.	रिवाड़ी	458.68
19.	महेन्द्रगढ़	237.81
	कुल जोड़	8636.41

Sample of Medicines

85. Sh. Anil Vij: Will the Minister of State for Health be pleased to state-

(a) whether any samples of Medicines have been taken during the last five years; if so, the districtwise and yearwise details thereof;

(b) the number of samples out of those referred to in part (a) above have been failed, together-with the action taken in this regard; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to check the sale of spurious medicines in the State?

राज्य स्वास्थ्य मंत्री (डॉ० एम०एल० रंगा):

(ए) हां, पिछले पांच वर्षों में जिलावार तथा सालाना, नियमित लिए गए नमूनों का विवरण अनैक्चर-1 पर है।

(बी) (i) कुल 785 नमूने निम्न स्तर के तथा मिलावटी पाए गए हैं जोकि अनैक्चर-I पर दर्ता किये गए हैं।

(ii) मिलावटी/सपूरियस पाए गए सभी नमूनों के मामलों में मुकदमा दायर करने के आदेश दिए हुए हैं जिनमें से 83 मामलों में मुकदमें पहले ही विभिन्न न्यायालयों में दायर किए जा चुके हैं और 38 मामलों की छानबीन की जा रही है। 339 मामलों में विभाग द्वारा औशधि एवं प्रसाधन नियम 1940 तथा नियमावली 1945 के अंतर्गत हरियाणा राज्य में स्थित औशधि निर्माताओं के विरुद्ध आवेदन कार्यवाही की जा चुकी है। 325 मामले बाहर के राज्यों में स्थित उनके औशधि निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु भेजे जा चुके हैं।

(iii) राज्य में सपूरियस दवाईयों के चेक के लिए निम्नलिखित पग उठाये जा रहे हैं।

(i) जिला औशधि निरीक्षकों को दवाईयों की दुकानों/आर0एम0पीज0 से प्रति मास 12 नमूने लेने की हिदायत जारी की हुई है।

(ii) वरिष्ठ औशधि निरीक्षकों को भी औशधि निर्माताओं से प्रति मास पांच नमूने लेने होते हैं।

(iii) दवाईयों की दुकानों पर विशेष छापे मारे जा रहे हैं।

ANNEXURE-1

Details of samples taken District wise/year wise

Name of the District	Year 1997-98	Year 1998-99	Year 1999-2000	Year 2000-2001	Year 2001 up to December
1	2	3	4	5	6
Ambala	110	232	283	323	227
Bhiwani	96	115	123	101	29
Faridabad	109	128	236	223	215
Fatehabad	70	63	112	115	73
Gurgaon	121	157	217	227	193
Hisar	104	316	354	356	212
Jind	95	87	108	163	81
Jhajjar	60	12	-	35	134
Kurukshetra	70	83	114	54	91
Kaithal	94	79	47	6	83
Karnal	102	149	189	160	151
Narnaul	50	9	15	15	-
Panipat	106	79	128	868	102

Panchkula	90	42	72	95	86
Rohtak	110	197	172	165	98
Rewari	86	108	136	127	94
Sirsa	90	11	120	92	39
Sonepat	216	69	148	129	93
Yamunanagar	96	137	139	132	132
Total	1875	2073	2713	2646	2133

ANNEXURE-II

Details of samples declared not of standard quality

Year	Sub standard	Adultrated/spurious
1997-98	135	12
1998-99	102	31
1999-2000	110	30
2000-2001	173	16
2001 upto December	144	32
Total	664	121

Details of samples declared a not of standard quality (District wise)

Name of the	Year	Year	Year	Year	Year

District	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001 upto December
1	2	3	4	5	6
Ambala	12	20	13	23	7
Bhiwani	8	4	7	9	2
Faridabad	9	8	7	9	13
Fatehabad	-	1	-	9	9
Gurgaon	11	7	7	12	28
Hisar	20	7	28	30	19
Jind	-	3	18	8	2
Jhajjar	-	-	-	2	5
Kurukshetra	11	9	4	3	12
Kaithal	3	5	3	1	5
Karnal	4	5	8	14	6
Narnaul	2	1	2	-	1
Panipat	8	1	6	4	2
Panchkula	8	1	5	10	4
Rohtak	19	28	17	26	10

Rewari	11	3	11	8	20
Sirsa	8	11	2	2	8
Sonepat	3	6	6	8	8
Yamunanagar	9	4	-	10	22
Total	146	124	144	188	183

Amount Spent on Old Age Pension

86. Sh. Nafe Singh Rathi: Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state the details of amount of old-age, disabled and widow pension disbursed during the period from 1st April, 1991 to 31st March, 1996, from 1st April, 1996 to 31st July, 1999 and from 1st August, 1999 to 10th Feb., 2002?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (चौधरी रिसाल सिंह): ब्यौरा इस प्रकार से है:—

अवधि	वृद्धावस्था पै न खर्चा	विधवा पै न खर्चा (करोड़ों में)	विकलांग पै न खर्चा	कुल योग
1	2	3	4	5
(I) 1-4-1991 से 31-3-1996				
1991-92	60.18	16.40	3.62	80.20

1992-93	71.33	13.68	3.08	88.09
1993-94	54.36	13.66	3.93	71.95
1994-95	114.22	17.87	3.94	136.03
1995-96	80.14	17.84	3.96	101.94
(II) 1-8-1999 से 10-2-2002				
1996-97	83.88	23.52	4.44	111.84
1997-98	81.82	26.89	4.66	113.37
1998-99	82.88	27.64	5.11	115.63
1-4-1999 से 31-7-1999	33.17	12.36	2.28	47.81
योग	281.75	90.41	16.49	388.65
(III) 1-8-1999 से 10-2-2002				
1-8-1999 से 31-3-2000	90.99	28.30	5.25	124.54
2000-2001	221.35	67.08	13.13	301.56
1-4-2001 से	187.62	61.20	12.93	261.75

10-2-2002				
योग	499.96	156.58	31.31	687.85

Amount Spent on the Construction of Harijan Chaupals

87. Shri Nafe Singh Rathi: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the constituency wise number of S.C. and B.C. Chaupals constructed in the state during the period from 1st April, 1991 to 31st March, 1996, from 1st April, 1996 to 31st July, 1999 and from 1st August, 1999 to 10th Feb., 2002;

(b) the Constituency wise number of Chaupals in the State for which the amount has been sanctioned in the "Sarkar Apke Dwar" programme?

Inerim Reply

OM PARKASH CHAUTALA

D.O.

No.

CHIEF MINISTER,

HARYANA

Chandigarh, Dated 5th

March, 2002

Subject: Unstarred Assembly Question No. 87.

Respected Speaker

Sh. Nafe Singh Rathi, M.L.A. vide Question No. 87 asked the following Question:

(a) the constituency-wise number of S.C. and B.C. Chaupals constructed in the State during the period from 31st April, 1991 to 31st March, 1996, from 1st April, 1996 to 31st July, 1999 and from 1st August, 1999 to 10th Feb., 2002;

(b) the constituency wise number of Chaupals in the State for which the amount has been sanctioned in “Sarkar Apke Dwar” programme?

The information regarding the number of constituency wise S.C. and B.C. Chaupals got constructed in the above said period will have to be collected from the field offices in the State, and collection of requisite information in such a short span of period is not possible. It is, therefore, requested that atleast six weeks time may kindly be granted so that desired information is collected from the field agencies.

Yours Sincerely,

Sd/-

(Om Parkash

Chautala)

Shri Satbir Singh Kadian,

Hon'ble Speaker,

Haryana Vidhan Sabha.

Road Constructed by H.S.A.M.B.

88. Shri Nafe Singh Rathi: Will the Minister for Agriculture be pleased to state the constituency wise details of new roads in Kilometers constructed, reconstructed and

repaired by the Haryana State Agricultural Marketing Board in the villages of Haryana during the period from 1st April, 1991 to 31st March, 1996, 1st April, 1996 to 31st July, 1999 and 1st August, 1999 to 10th Feb., 2002 togetherwith the expenditure incurred thereon?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू): हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य में सड़कों के निर्माण पुनः तथा मरम्मत व इन पर खर्च का विवरण निम्न प्रकार है:—

अवधि	नई सड़कों का निर्माण		पुनः निर्मित सड़कें		मरम्मत की सड़कें	
	लम्बाई (कि०मी० में)	खर्च (करोड़ों में)	लम्बाई (कि०मी० में)	खर्च (करोड़ों में)	लम्बाई (कि०मी० में)	खर्च (करोड़ों में)
1-4-91 से 31-3-96	1950.74	71.40	—	—	385.61	3.72
1-4-96 से 31-7-99	903.81	44.89	8.19	0.30	1249.28	22.21
1-8-99 से	2819.96	208.53	2.80	0.17	3677.95	137.55

10-2-02						
---------	--	--	--	--	--	--

निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा तैयार करने हेतु समय व श्रम की तुलना में इससे विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा।

School upgraded in the State

89. Sh. Nafe Sing Rathi: Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) the yearwise number of Schools upgraded in the State during the period from 1st April, 1991 to 31st March, 1996.

(b) the total number of new rooms constructed by the Govt. in the Govt. Schools referred to in part (a) above.

(c) the constituency wise number of rooms constructed in the Govt. Schools by the Haryana Govt. during the period from 1st April, 1996 to 31st July, 1999 and 1st August, 1999 to 10th Feb., 2002 respectively, together-with the Schools upgraded during the said period in the State;

(d) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Government School in the State during the next academic Session especially in Bhadurgarh Constituency?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह):

(क) राज्य में वर्षवार 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1996 तक जिन विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया है उनका विवरण निम्नानुसार है।

1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
161	152	79	258	458

(ख) राजकीय विद्यालयों में 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1996 समय के दौरान नये निर्मित किये गये नये कमरों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:-

1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
101	166	188	253	297

(ग) हरियाणा सरकार द्वारा विद्यालयों में विधान सभा क्षेत्रवार नये निर्मित किये गये कमरों की संख्या 1 अप्रैल, 1996 से 31 जुलाई, 1999 और 1 अगस्त, 1999 से 10 फरवरी, 2002 तक अनुबन्ध "क" अनुसार है 4/96 से 7/99 के दौरान स्तरोन्नत किये गये विद्यालयों की संख्या 736 तथा 8/99 से 10-2-2002 तक स्तरोन्नत किये गये विद्यालयों की संख्या 349 है।

(घ) राज्य में वर्ष 2001-2002 के दौरान 91 विद्यालयों को स्तरोन्नत किया गया था। यह विद्यालय नये सत्र से कार्य आरम्भ कर देंगे। 146 विद्यालयों का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें से 9 विद्यालय (3 प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक

विद्यालय, 3 माध्यमिक से उच्च विद्यालय तथा 3 उच्च विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय) बहादुरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में है। निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार कमरें बनाने की सूचना निम्नानुसार है।

अनुबन्ध-क

जिला

अम्बाला	अम्बाला भाहर	अम्बाला छावनी	नग्गल	नारायण गढ़	मुलान ा	कुल
4 / 96 से 7 / 99	29	03	13	03	05	53
8 / 99 से 10-2-200 2	08	01	10	15	17	51
कुरुक्षेत्र	थानेसर	पेहवा	भाहबाद			
4 / 96 से 7 / 99	05	—	02	—	—	07
8 / 99 से 10-2-200 2	02	—	01	—	—	03

भिवानी	भिवानी	बवा नी खेड़ ा	बा ढ डा	दादरी	तो ा म	लोहारू	मुण्डा ल	
4 / 96 से 7 / 99	06	11	04	05	16	—	06	48
8 / 99 से 10-2-200 2	—	12	09	—	—	09	—	80
रोहतक	रोहतक	महम	कलानौर	हसनग ढ	किलो ई			
4 / 96 से 7 / 99	02	07	07	02	05	23		
8 / 99 से 10-2-200 2	—	04	05	02	07	18		
फरीदाबाद	फरीदाबा द	मेवला महाराजपु र	बल्लब गढ़	पलव ल	हसनपु र	हथीन		

4 / 96 से 7 / 99	2	—	2	8	—	25	37
8 / 99 से 10-2-200 2	15	8	6	4	6	21	60
झज्जर	झज्जर	बेरी	बादली		सालहा वा	बहादु रगढ	
4 / 96 से 7 / 99	28	11	10		28	1	78
8 / 99 से 10-2-200 2	22	18	63		11	10	124
नारनौल	नारनौल	अटेली	महेन्द्रगढ				
4 / 96 से 7 / 99	1	1	—				2
8 / 99 से 10-2-200 2	12	20	5				37

पानीपत	पानीपत	समालखां	नौलथा				
4 / 96 से 7 / 99	11	70	26				107
8 / 99 से 10-2-200 2	18	53	29				100
रिवाड़ी	रिवाड़ी	बावल	जाटूसाना				
4 / 96 से 7 / 99	41	100	56				197
8 / 99 से 10-2-200 2	4	26	6				100
8 / 99 से 10-2-200 2	15	8	6	4	6	34	60
हिसार	हिसार	हांसी	आदम पुर	धिराये	बरवाला	नारनौ द	
4 / 96 से	—	43	5	105	21	13	187

7 / 99							
8 / 99 से 10-2-200 2	4	28	16	49	41	16	154
फतेहाबाद	फतेहाबा द	भटूकलां	टोहाना		रतिया		
4 / 96 से 7 / 99	5	14	1		—		20
8 / 99 से 10-2-200 2	32	21	66		27		146
सिरसा	सिरसा	रोड़ी	डबवाली		दड़बा कला	ऐलना बाद	
4 / 96 से 7 / 99	—	—	—		—	—	
8 / 99 से 10-2-200 2	10	181	55		16	44	306

यमुनानगर	यमुनानगर	छछरौली	सढौरा		जगाधर ी	रादौर	
4 / 96 से 7 / 99	3	11	—		9	1	24
8 / 99 से 10-2-200 2	41	20	63		40	32	196
करनाल	करनाल	नीलोखेड़ ी	इन्द्री	जुंडल ा	घरौन्डा	असंध	
4 / 96 से 7 / 99	7	7	8	2	—	9	33
8 / 99 से 10-2-200 2	14	20	6	15	20	37	112
गुड़गांव	गुड़गांव	सोहना	पटौदी	नूंह	फिरोज पुर झिरका	तावडू	
4 / 96 से 7 / 99	6	9	6	4	3	3	31

8 / 99 से 10-2-200 2	5	5	6	—	—	2	18
सोनीपत	सोनीपत	राई	रोहट	कैला ना	गोहाना	बरोदा	
4 / 96 से 7 / 99	15	3	15	44	3	1	81
8 / 99 से 10-2-200 2	—	16	18	39	12	6	91
पंचकूला	कालका						
4 / 96 से 7 / 99	37						37
8 / 99 से 10-2-200 2	—						
जीन्द	जीन्द	नरवाना	सफीदों	जुला ना	उचाना कलां		

4 / 96 से 7 / 99	24	10	8	15	11		68
8 / 99 से 10-2-200 2	6	31	25	3	7		72
कैथल	कैथल	राजोंद	कलाय त	पाई	गुहला चीका	पुण्डर ी	
4 / 96 से 7 / 99	7	8	16	6	7	3	47
8 / 99 से 10-2-200 2	8	9	13	16	4	8	58

Closure of Bus Depot Charkhi Dadri

90. Sh. Jagjit Singh: Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Depot of Haryana Roadways, Charkhi Dadri has been closed; if so, the reasons thereof togetherwith date of its closure?

परिवहन मंत्री (श्री अ गोक कुमार): दादरी डिपो को बन्द नहीं किया गया है, इसे केवल 1 अप्रैल, 2001 से भिवानी डिपो का उप-डिपो बनाया गया है। यह निर्णय भिवानी, दादरी व

झज्जर क्षेत्र के लोगों को और अच्छी परिवहन सेवायें प्रदान करने तथा विभाग की परिचालन एवं वित्तीय कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिये लिया गया था।

Repair of Samaspur-Imlota Road

91. Sh. Jagjit Singh: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the Road from Samaspur to Imlota via Bhagvi located in Dadri Sub-division; and

(b) if so, the time by which the said road referred to in part (a) above is likely to be repaired?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) हां, श्रीमान जी। कार्य प्रगति पर है।

(ख) गांव सरूपगढ़ में अतिक्रमण हटाने के 3 मास के अन्दर सड़क की पूरी तरह से मरम्मत कर दी जाएगी।

Leakage in Kitlana Distributory

92. Sh. Jagjit Singh: Will the Chief Minister be pleased to state the steps being taken by the Government to check the leakage from Charkhi to Iktayrapura Head of Kitlana distributory, Dadri Sub Division; if so, the time by which the said leakage is likely to be checked?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): गांव चरखी से इकतयारपुर तक कितलाना रजवाहे में रिसाव जोड़ों के चूने का कारण है। धन की उपलब्धता पर जोड़ों को भरने का कार्य भुरु कर दिया जाएगा।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, आज तो इन लोगों को सहयोग करना चाहिए था। (गोर एवं व्यवधान)

भाोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, दो महान विभूतियां इस संसार से चली गई हैं, मैं आपकी अनुमति से उनके लिए हाउस में भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप प्रस्ताव करे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: यह सदन 7 मार्च, 2002 को भाहीद हुए गांव बहलम्बा रोहतक के सिपाही श्री राजबीर राठी और 9 मार्च, 2002 को गांव कोसली जिला रिवाड़ी के स्वतंत्रता सेनानी श्री राय सिंह के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है। उनके निधन से एक वीर सिवाही तथा स्वतन्त्रता सेनानी और देशभक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगतों के भाोक संतप्त के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौधरी भजन लाल (आदमपुर): लीडर ऑफ दि हाउस ने जो प्रस्ताव रखा है मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से इस भाोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ तथा दुखी परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। इस भाोक प्रस्ताव को पास किया जाए।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है, मैं अपने आप को तथा अपनी पार्टी को भी इसमें शामिल करता हूँ तथा इन भाोक प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आनॅरेबल मैम्बर्ज, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है मैं भी उसके साथ अपने को जोड़ता हूँ और भाोक संतप्त परिवारों को विधान सभा की ओर से रैजोल्यूशन भेज दिया जाएगा। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं की भाांति के लिए आप अपनी-अपनी सीटों पर दो मिनट के लिए मौन के लिए खड़े हों।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पंजाब क्षेत्र में एस0वाई0एल0 कैनल की पूरा करने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice from Shri Anil Vij, M.L.A. regarding completion of S.Y.L. in Punjab Territory. I admit it. He may read his notice.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिए जाने तथा अब पंजाब सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पटी 11) रद्द होने से हरियाणा सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी आने का मार्ग प्रोत्साहित हो गया है। जिसके लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है तथा सारा प्रदेश खुशियां मना रहा है। लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। हरियाणा की वर्षों से प्यासी धरती की प्यास बूझेगी। किसान खुशहाल होगा। राज्य का बहुमुखी विकास होगा। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के नेताओं द्वारा रोजाना दिए जा रहे बयानों तथा सतलुज यमुना लिंक नहर के संबंध में नव-निर्वाचित कांग्रेस सरकार तथा उनके मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए विरोधी स्टैंड से हरियाणा की जनता के मन में भ्रम और भय व्याप्त है। यहां यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि आज से पहले जब भी हरियाणा के हितों का मामला आया है, केन्द्र सरकार ने हमें पंजाब राज्य का पक्ष लिया है। जो लोगों में अधिक चिंता का कारण बना हुआ है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य दें।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों को अवगत करवाना चाहूंगा और माननीय सदस्य ने यह जो जानना चाहा है कि सतलुज यमुना लिंक नहर के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पंजाब के नेताओं द्वारा इस नहर विरोधी स्टैण्ड से हरियाणा की जनता के मन में भय व्याप्त है तथा केन्द्र सरकार ने सदा पंजाब के लोगों का साथ दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जनवरी, 2002 को जो ऐतिहासिक फैसला दिया है उसमें यह निर्देश दिया है कि पंजाब सरकार 15 जनवरी, 2002 से एक वर्ष के अन्दर-अन्दर इस लिंक नहर का निर्माण पूरा करें तथा केन्द्र सरकार को भी यह निर्देश दिया है वह अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करते हुए यह देखे कि यदि पंजाब सरकार एक वर्ष के अन्दर-अन्दर नहर का निर्माण पूरा नहीं कर पाती है तो केन्द्र सरकार अपनी ऐजेन्सियों द्वारा भीघ्राति विघ्न इस नहर का निर्माण पूरा करवाए। अध्यक्ष महोदय, यह भांका बेबुनियाद है कि केन्द्र सरकार हरियाणा के हितों की अनदेखी करेगी तथा पंजाब सरकार का साथ देगी। वर्तमान केन्द्र सरकार का रवैया हरियाणा विरोधी कभी नहीं रहा है। सरकार को पूरा विश्वास है कि मौजूदा केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को बिना किसी भेदभाव के पूरा करेगी। मैं इस मामले में प्रधान मंत्री जी से मिला था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष का समय पंजाब सरकार को इस कार्य को पूरा करने के लिए दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का

फैसला मानने के लिए पंजाब सरकार व केन्द्र सरकार दोनों ही बाध्य हैं। हमें केन्द्र सरकार से इस विषय पर पूर्ण न्याय की आशा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है तथा इस पर समय-समय अपना दायित्व निभाती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने सतलुज यमुना लिंक नहर का जो हिस्सा हरियाणा में पड़ता है उसका सर्वेक्षण, पूरा करा लिया है। इस कार्य पर 12 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है। पश्चिमी यमुना नहर के आऊटफाल से मुनक तक मरम्मत के लिए 8 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

श्री कर्ण सिंह दलाल:

श्री अध्यक्ष: कर्ण सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (गोर एवं व्यवधान) ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हरियाणा के हिस्से में नहर के हिस्से के निर्माण कार्य को अति भीघ्न पूरा किया जा सके। मैं मानीय सदन को यह आवासन देना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार हरियाणावासियों के हितों की रक्षा हर सम्भव कीमत पर करेगी तथा सदा अपनी क्षमता एवं भावित के अनुसार हमें आशा इस दिशा में प्रयत्न जारी रखेगी ताकि हरियाणा प्रदेश की भूमि पर

रावी व्यास का पानी अति गीघ्र पहुंच सके। हमें आ ता है कि हरियाणा के लिए यह नहर एक वरदान साबित होगी और हरियाणा को भीघ्र ही समृद्ध गाली एवं खु गहाल बनाएगी।

श्री अध्यक्ष: अब अनिल विज अपनी सप्लीमेंट्री पूछेंगे।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मुझे भी इस बारे में कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष: भजनलाल जी, आप बैठें। पहले अनिल विज ने अपनी सप्लीमेंट्री पूछनी है।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, हम भी इस बारे में अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: ये अब जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (गोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि कालिंग अटैं गन मो गन पर कौन सप्लीमेंट्री पूछ सकता है?

श्री अध्यक्ष: जिसका नोटिस होगा अपनी सप्लीमेंट्री कुछ पूछ सकता है।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, और सदस्य भी इस बारे में अपना सवाल पूछ सकते हैं?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, ये इस मामले में सीरियस नहीं हैं अगर ये सीरियस होते तो ये भी इस बारे में अपना कालिंग अटैंशन मोशन या कोई दूसरा नोटिस देते लेकिन ये इस बारे में कुछ भी हाउस में लेकर नहीं आए हैं। (गोर एवं व्यवधान) They are not serious.

श्री अध्यक्ष: मेरा सभी महानुभावों से निवेदन है कि वे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं।

प्रो० सम्पत सिंह: They have missed the train इसलिए स्पीकर सर, ये अब खड़े हो रहे हैं इनकी इस मामले में कोई सीरियसनैस नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रघुबीर सिंह कादयान: स्पीकर सर,

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: जो भी सदस्य बिना परमीशन के बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सम्पत सिंह जी हर बात पर वैसे ही खड़े हो जाते हैं। ये घटिया बात कर रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह घटिया भाब्द हाउस की कार्यवाही से निकलवाया जाना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, अभी आपको इस बारे में पता नहीं है कि किस समय पर क्या बोलना चाहिए। हालांकि आपको इस बारे में बहुत बताया गया है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आप इनकी क्लास लिया करें। (गोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर साहब, यह बहुत सीरियस इजु है आप रूल 73-ए के तहत इस मामले पर भाोट नोटिस डिसकान करवा लें। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, ये लोग आपकी फिराखदिली का फायदा उठा रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान) जब इनकी पार्टी के सारे लोगों ने काली टोपी पहन रखी है तो भजनलाल जी काली टोपी क्यों नहीं पहन रहे हैं। ये भी काली टोपी पहनकर दिखाएं। क्या यह टोपी इनके सिर के मुताबिक छोटी हो गयी है? (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, क्या मैं बोल सकता हूँ?

श्री अध्यक्ष: ठीक है, पहले आप ही बोलें।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि प्रदेश के हित में और सरकार के हित में क्या है, इस बारे में

में कहना चाहूंगा। अभी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक साल में एस0वाई0एल0 नहर पंजाब बनाएगा।

श्री अध्यक्ष: भजनलाल जी, आप तो फिर उसी बात पर आ रहे हैं मैं तो सोच रहा था कि आप कुछ और बात कहेंगे। इसलिए अब आप बैठें।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, अब आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो भजनलाल जी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इस कालिंग अटैंटन मोशन पर केवल अनिल विज ही अपनी सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं लेकिन फिर भी मैं पूरे सदन को इस बात के लिए आवासन देना चाहूंगा कि जब मैं अपनी रिप्लाय दूंगा उस समय मैं एस0वाई0एल0 के मुद्दे को पूरी तरह से उजागर करूंगा उसके बाद किसी की कोई भांका नहीं रह जाएगी।

चौधरी भजन लाल: अगर ऐसा है तो अच्छी बात है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मेरा निवेदन है कि आप हमें इस तरह के मोशन का जवाब समय पर तो दिलवा दिया करें ताकि हम उसका पढ़ सकें। इसको पढ़ने के बाद अगर

कोई सदस्य उस पर कुछ पूछना चाहें तो वह पूछ सकता है।
(गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस कालिंग अटैं इन का जवाब आ गया है इसलिए अब आप बैठें।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, इसका जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: इसका हाउस में दे दिया गया है। जिसका कालिंग अटैं इन मो इन है उनके पास इसका जवाब है और वे इस बारे में सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं। इसलिए अब आप बैठें। (गोर एवं व्यवधान) अनिल विज पूछ रहे हैं उनको पूछने दे मैंने तो सोचा था कि दो तीन दिन की छुट्टी थी कुछ तो असर हुआ होगा। आपने इस बारे में बात करनी हो तो मेरे चैंबर में आकर अलग से बात कर लें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आज हमने काली टोपी पहन रखी है उसके बारे में आपने पूछा नहीं कि क्यों लगा रखी है।

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल ने काली टोपी का जिक्र किया। गांधी जी की सफेद टोपी

को कांग्रेस के काले कारनामों ने काला कर दिया। परमात्मा इन भाइयों को सदबुद्धि दे इन्होंने टोपी तो अपनाई है अब ये गांधी जी के पदचिन्हों पर भी चलना शुरू कर दें।

चौधरी भजन लाल: रोश प्रद न के लिए काली टोपी लगाई जाती है।

श्री अध्यक्ष: मुझे कोई ऐतराज नहीं है चाहे आप काले कपड़े पहने। आप काला कर्ता पजामा पहनेंगे तो भी मैं बिल्कुल नहीं उतरवाऊंगा। विज साहब, आप अपनी सप्लीमेंट्री पूछें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सभी मेंबरज में बड़ा रोश है। (गोर एवं व्यवधान) जो सात मेंबरज सस्पेंड थे वे आज बोलेंगे। इसलिए एक दिन बजट के लिए आगे बढ़ाइए।

श्री अध्यक्ष: बी०ए०सी० की रिपोर्ट के हिसाब से आज चीफ मिनिस्टर साहब ने रिप्लाइ देनी है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजनलाल:

श्री अध्यक्ष: भजनलाल जी, जो कुछ भी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, हमें रिप्लाइ की कॉपी दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष: आप सब बैठ जाएं। (गोर एवं व्यवधान) मैं आपको रूल-73 पढ़कर सुनाता हूँ—

“There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the notice stands may, with the permission of the Speaker, ask a question.

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, आप बड़े ही काबिल और फिराखदिल स्पीकर हैं।

श्री अध्यक्ष: चलो अच्छा हुआ आपको सद्बुद्धि आ गई। (गोर एवं व्यवधान) आप भी काबिल बनो। चौधरी बंसी लाल जी की छोटी सी पार्टी है दो मैनबर हैं दोनों बोले हैं बैठ जाएं। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, वे कुछ ओर बात कर रहे हैं ये कुछ ओर बात कर रहे हैं सलाह तो कर लें।

श्री अध्यक्ष: आप सब बैठ जाएं। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, श्री अनिल विज जी बहुत सीनियर मैम्बर हैं और बहुत ही लोक महत्व का और पब्लिक हित का मुद्दा through Callinig Attention Motion इस सदन में उन्होंने उठाया है स्पीकर सर, सरकार की तत्परता देखिये कि आज सुबह

उन्होंने अपना Under Rule 73 Calling Attention Motion का नोटिस दिया और उसके तुरन्त बाद कोई टाईम लिये बिना और हाउस का एक सैकिण्ड भी गवायें बगैर सरकार ने उसका रिप्लाइ दिया। क्योंकि सारा प्रदे । इस बारे में चिन्तित है और एस0वाई0एल0 प्रदे । की लाईफ लाईन है। इस लिए सरकार ने इमीजियेट उसका रिप्लाइ दिया और माननीय विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि रूल 73 का रिप्लाइ सर्कुलेट नहीं हुआ। (गोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आपने रूलिंग दी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मेरी बात तो सुनिये।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। चौधरी सम्पत सिंह जी, मुझे बोलने दीजिये।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मेरी बात तो सुनिये। दलाल साहब, मैं स्पीकर साहब की परमी ।न से बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठिये। क्यों आप प्वायंट ऑफ आर्डर का मिसयूज कर रहे हैं?

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, आप सब कुछ ही मिस यूज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मिस यूज नहीं है बल्कि आप तो खुद कंप्यूज हो। (गोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हमी पार्टी ने भी अण्डर रूल-73 के तहत एस0वाई0एल0 के बारे में नोटिस दिया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशय है इस पर डिसकान जरूर होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आप अगर इतने चिन्तित होते तो आप यह नोटिस पहले देते। आपने 12 बजकर 22 मिनट पर यह नोटिस दिया है यह नोटिस आपको पहले देना चाहिये था पहले आप कहाँ गये थे? अब आप बैठ जाइये। इस विशय पर डिबेट भुरू हो चुकी है अगर आप इतने चिन्तित होते तो पहले नोटिस देते (गोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशय है इस पर डिसकान जरूर होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जायें।

श्री धर्मबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने कालिंग अटैंकान नोटिस समय पर दिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशय है इस पर डिसकान जरूर होनी चाहिये। आप इसको रद्द नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: अगर रद्द करने के काबिल होगा तो रद्द करेंगे और मंजूर करने की काबिल होगा तो मंजूर भी करेंगे। आप मौका चूक गये। अब अनिल विज को मौका दीजिये।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इन लोगों का अपना दायित्व बनता था अगर इनको इतनी चिन्ता होती तो ये कोई मोशन देते। माननीय सदस्य श्री अनिल विज सदन में कोई मोशन लेकर आये हैं तो उनकी बात को पूरा सुन नहीं रहे हैं बीच में इंटरप्शन कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाइ आ रहा है उसके बाद माननीय सदस्य अगर प्रदेशों के हित में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं यदि उनके दिमाग में कोई भांका है तो वह भांका भी प्रदेशों के हित में होगी और उसका जवाब भी प्रदेशों के हित में होगा। चौधरी भजन लाल जी भी एस0वाई0एल0 के बारे में जितना बोलना चाहते थे बोले, उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी भी उस विषय पर जितना बोलना चाहते थे, बोले, जो उन्होंने अपनी बात कहनी थी वह तो कह दी। बाकी सदस्य भी इस बारे में बोले थे, जो बात उन्होंने कहनी थी उन्होंने भी कही। इसके बाद बजट भी आयेगा उस पर भी बोलने का समय दिया जायेगा अगर उस पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं जहां तक मोशन का सवाल है मोशन पर सवाल या तो वह सदस्य पूछे जो मोशन लेकर आये हैं। वे इतने सीरियस थे तभी इसको समय पर लेकर आये हैं। स्पीकर सर, आपने रूल 73(2) के बारे में अपनी रूलिंग दी है लेकिन मैं रूल 73(1) के बारे में डिसकस

करना चाहूंगा In Rule 73(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, it is mentioned

“A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date.”

ब्रीफ स्टेटमेंट गवर्नमेंट उस पर दे not less than Chief Minister उसके बारे में हाउस के नेता ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरन्त उस बात का एकदम जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा सरकार की तत्परता और क्या होगी? श्री अनिल विज जो कॉलिंग अटैंडान्स लेकर आये हैं उसके बारे में वे सीरियस थे और अगर वे उस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उनको सवाल पूछने दें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे सकें and that will be in the interest of the State and in the interest of public, Sir.

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और इस सरकार का इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूँ कि इतने शॉर्ट समय में कॉलिंग अटैंडान्स एडमिट की गई और सरकार उसका उत्तर लेकर आई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं भी पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ इसलिए मैं इनको पढ़वाना चाहता हूँ। (गौर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप बैठें। (गौर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: क्योंकि मैम्बर के लिए मुख्यमंत्री महोदय का ब्यान आ गया है और वह रिकार्ड हो गया है। सिर्फ जो मैम्बर पूछता है उसके लिए ही रिप्लाइ है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान:

चौ० जय प्रका 1:

श्री अध्यक्ष: रघुबीर सिंह कादियान और जय प्रका 1 बरवाला की कोई बात रिकार्ड न कि जाए। हाउस में स्टेटमेंट आ चुकी है, उसे आपने गौर से सुना इसलिए इसे दिमाग में रखें। मैं नाजायज किसी को नहीं बोलने देता और जायज बात सबकी सुनता हूँ। इसलिए आप दोनों बैठें। रूल 73(1) और (2) पढ़कर देखें। (गौर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, आप इनको बिठाएं, ये बीच-बीच में मुझे इन्ट्रूट कर रहे हैं। Please listen me. Do not encroach upon my rights. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने

हमारे पक्ष में बहुत ही सुस्पष्ट निर्णय दिया है लेकिन अगर पिछला इतिहास देखें कि आज तक जब भी हमारे और पंजाब के बीच में चाहे वह सीमा विवाद रहा हो, या पानी के मामले की बात रही हो या भाह बानी कमी इन की रिपोर्ट हो या इन्दिरा समझौता हो या राजीव लॉंगोवाल समझौता रहा हो, मैथ्यू कमी इन रहा हो या पानी के बारे में केस हो, चाहे तीनों राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान मुख्यमंत्रियों की तरफ से की हुई सहमति की बैठक हो, जब-जब भी जिस-जिस ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया, पंजाब ने उस निर्णय को कभी भी नहीं माना है। देश में ऐसे भी अनेकों उदाहरण मौजूद हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और लोगों ने न माना हो तो केन्द्र सरकार ने बिल लाकर उस निर्णय को निरस्त करवाया, भाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था लेकिन केन्द्र सरकार ने उसके विरुद्ध निर्णय लेकर उसको निरस्त किया। इसलिए लोगों की भांका निर्मूल नहीं है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सबके बावजूद भी पिछले इतिहास को देखते हुए कि पंजाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करता और जैसा कि पंजाब सरकार के नेताओं के ब्यान रोज दूसरों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने के बारे में आते हैं वहीं उनके खुद के निर्णय के विरुद्ध ब्यान आ रहे हैं। यदि फिर भी पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अमल नहीं करती तो हमारी सरकार किस प्रकार से अपने को तैयार कर रही है यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ? स्पीकर सर, दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहर बनाने

का निर्णय दे दिया क्या पानी का भी निर्णय कर दिया कि कितने एम0ए0एफ0 पानी हमें मिलेगा। (विधन) तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि पंजाब में कितने किलो मीटर नहर बनी हुई है और कितनी अधूरी है और जो अधूरी है वह एक साल में बन सकती है या नहीं?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा न सिर्फ सम्मानित सदस्य श्री अनिल विज को बल्कि पूरे सदन को इस अहम विषय से अवगत करवाना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पंजाब को मानना ही पड़ेगा। आज तक कोई ऐसी मिसाल देखने और सुनने में नहीं आई कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को किसी ने न माना हो। जहां तक पानी का संबंध है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इंटरिम रिपोर्ट 3.83 एम0ए0एफ0 पानी की आ गई है कि हमें 3.83 एम0ए0एफ0 पानी मिलेगा। इस बारे में मुकम्मल रिपोर्ट बाकी है। वह भी आयेगी इस मामले में मेरे माननीय साथी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे की बजाए एक और अहम मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुद्दा है वह प्रदेशों के स्तर का नहीं बल्कि पूरे देश के स्तर पर जुड़ा हुआ है पंजाब के फैसले से पहले यह फैसला आ जायेगा और एक साल के अर्से में निश्चित रूप से यह नहर बन जायेगी अब तो साल भी नहीं है 15 जनवरी से 365 दिन का (एक साल का) समय निश्चित हुआ था, अब तो एक साल से भी कम समय रह गया है। जिस समय सुप्रीम

कोर्ट का फैसला आया उस समय पंजाब के सभी राजनैतिक दल कह रहे थे कि रिट्यू करेंगे, वह रिट्यू भी खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में भी रिट्यू खारिज हो गया इसलिए इस बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा और निश्चित रूप से एक साल के अंदर-अंदर नहर बन जायेगी इसलिए सारी तैयारी हम पहले से ही कर रहे हैं। हम चौधरी बंसी लाल जी की तरह कमीशन खाने के लिए पहले काम नहीं करवा रहे बल्कि जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि काम जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो जाये।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मेरा सबमिशन यह है कि कमीशन मुख्यमंत्री जी खाते हैं, मैं नहीं खाता। ये कह रहे हैं कि इसकी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट फाइनल नहीं है, यह रिपोर्ट फाइनल है। इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को ये बदल नहीं सकते, उसमें क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं।

वक्तव्य—उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (पुनरारम्भ)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी इसी सदन में दुर्भाग्य से यहां बैठा करते थे और मैं विपक्ष में बैठा करता था। उस वक्त भी एक बात मैं कहता था कि चौधरी साहब इंजीनियर इन चीफ श्री पाठक साहब के कहने के बावजूद भी आपने नहर का काम गोदबलावा से भुरु

क्यों किया? अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने अपने समय में इस नहर का काम टेल से भूरु करवाया। ये सीनियर मैंबर हैं क्या इनको मालूम नहीं कि ड्रेन का काम टेल से भूरु होता है और नहर का काम मुड से होता है, ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है। इंजीनियर ने इन्हें सलाह भी दी थी कि नहर का काम मुड से भूरु किया जाये लेकिन उसकी बात नहीं मानी। अध्यक्ष महोदय, जितनी नहर पंजाब में बननी थी वह पंजाब सरकार ने बनवानी थी उसका कमी इन इन्हें नहीं मिलना था इसलिए इन्होंने जो नहर हरियाणा में बननी थी, उसको बनाना भूरु कर दिया क्योंकि उसका कमी इन इनको मिलना था। इन्होंने उस समय करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिये।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, न मैंने कमी इन खाया और न मैंने कमी इन खाना सीखा। कमी इन खाने का काम मुख्यमंत्री जी का है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, स्वयं चौधरी बंसी लाल जी परसों अपनी बात की कंट्राडिक्ट इन कर गये। पहले जब हम कहते थे कि हरियाणा में पहले नहर नहीं बननी चाहिए उस समय ये कहते थे कि नहर बननी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि पहले मुरम्मत नहीं होनी चाहिए। इनकी कौनसी बात ठीक है। उस समय हम कहते थे कि ये कमी इन खाने के लिए नहर टेल से बनवा रहे हैं और अब ये उल्टा हमें कह रहे हैं कि मुरम्मत नहीं

होनी चाहिए। जिस समय चौधरी देवी लाल जी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले गये थे उस समय बंसी लाल जी कहते थे कि गलत किया, कोर्ट में तो 10 साल लग जायेंगे फिर इन्होंने इसकी सराहना की कि बहुत अच्छा किया। ये अपनी एक बात पर नहीं रहते।

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: बंसी लाल जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, नहर की मुरम्मत न करने के बारे में चौधरी बंसी लाल जी ने परसों यहां कहा है और यह रिकार्ड में है। मैं तो यहां नहीं था लेकिन चौधरी भजन लाल जी थे, ये ही बता देंगे।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह तो हम भी कहते हैं कि पहले मुरम्मत नहीं होनी चाहिए। जब तक पंजाब में नहर नहीं बनती तब तक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे चौटाला साहब ने बंसी लाल जी को कमीशन खाने के बारे में कहा वैसे ही अब ये कमीशन खाना चाहते होंगे। जब पंजाब में नहर बन जाये उस समय मुरम्मत शुरू करनी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, पंजाब में नहर 95 प्रतिशत बन चुकी है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, वह सारी नहर टूट गई हैं दोबारा बनानी पड़ेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, एक साल के अंदर—अंदर पंजाब के अंदर नहर बन जायेगी इसका हमें विश्वास है। उससे पहले हम अपने यहां मुरम्मत भी करेंगे क्योंकि बंसी लाल जी ने यह नहर पहले बनवा दी और अब उसमें गादड़ बिया गये हैं उन्होंने सारी नहर खोद डाली है, अगर उसकी मुरम्मत नहीं करेंगे तो पानी कैसे चलेगा। इसके अतिरिक्त हम माईनर डिस्ट्रीब्यूट्रियां भी बनायेंगे ताकि एक साल बाद दक्षिणी हरियाणा को भी दना—दन पानी मिल सके।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से 1 साल के अंदर यह नहर बननी है। इस एक साल की अवधि में से अब तक 60 दिन तो निकल चुके हैं और अभी तक इस पर कोई काम भी भुरू नहीं हुआ है। (विधन) इस बारे मेरा कहना यह है कि आपको चाहे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शन लेनी पड़े, अगर पंजाब में इस नहर पर 3—4 महीने में काम भुरू नहीं होता तो आपको आगे की सोच कर कोई बात नहीं करनी होगी।

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी, आप तो स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट रिकार्ड नहीं होगी।

चौधरी भजन लाल: मैंने क्या गलत बोल दिया है जो रिकार्ड नहीं करोगे।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं। (गोर एव विधन)

चौधरी भजन लाल: यह आपकी क्या समझ है।

श्री अध्यक्ष: आप में अच्छी समझ है। आप में अच्छी समझ दिख रही है, आप में अच्छी समझ लग रही है। (विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्पीकर साहब, अगर ये लोग समझदार होते तो ये लोग इस जगह न बैठे होते। (गोर एवं विधन) भजन लाल जी इसमें आपको क्या चिन्ता है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, नहर को पंजाब सरकार ने बनाना है। पंजाब में आपकी सरकार है। आप भी प्रयास करो कि वे जल्दी नहर बनवा दें। (गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल: पहले आपके बादल की सरकार थी तो उस वक्त आपने इसे क्यों नहीं बनवा लिया। (विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: हां, पहले जब हमारी सरकार थी तो हमने इस नहर के बनवाने का काम बी०आर०ओ० के सुपर्द कर दिया था। (गोर एवं विधन) फिर बाद में जब आपकी सरकार आई तो आपने इसको विदड्रा कर लिया। (गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल: आपने कब बी०आर०ओ० को सुपर्द कर दिया था। (गोर एवं विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी जब उप प्रधान मंत्री थे, चन्द्र भोखर जी प्रधान मंत्री थे और मैं मुख्यमंत्री था तो उस वक्त हमने इस नहर को बनवाने का काम बी०आर०ओ० के सुपर्द कर दिया था और इस पर काम भुरू हो गया था। बाद में आपकी सरकार आ गई और आपने उसको विदड़ा कर लिया। (गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल: उस वक्त तक तो कोई फैसला नहीं हुआ था कि (गोर एवं विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: आप यह बताएं कि आपने इसे उस वक्त विदड़ा क्यों किया। (गोर एवं विधन)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप बैठिये। (गोर एवं विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: आपको यह काम विदड़ा नहीं करना चाहिए था। (विधन)

श्री अध्यक्ष: अब आप सभी बैठ जाएं। अब गवर्नर एड्रैस पर मुख्यमंत्री जी अपनी रिप्लार्ड देंगे। (गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, हमारे जो मैम्बर्ज सदन में उपस्थित नहीं थे, उनको अब आप गवर्नर एड्रैस पर पहले बोलने का मौका दे दें, उसके बाद सी०एम० साहब अपना रिप्लार्ड दे देंगे। (गोर एवं विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: आपकी पार्टी को जितना समय देना चाहिए था वह स्पीकर साहब की तरफ से पहले ही दिया जा चुका है। (गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल: हमारे मैम्बरों को पहले आप बोलने का समय दे दें। (गोर एवं विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: नहीं, अब कोई समय नहीं मिलेगा। (गोर एवं विधन)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठ जाएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अब कोई समय नहीं मिलेगा। (गोर एवं विधन) बी०ए०सी० की मीटिंग में आप उपस्थित थे। उस में बाकायदा तय हुआ था कि मैंने 11 तारीख को रिप्लाइ देना है।

चौधरी भजन लाल: ठीक है, आपने रिप्लाइ देना है। मेरा कहना यह है कि जिन मैम्बरों को निकाल दिया गया था पहले उनको आप बोल लेने दें फिर आप अपनी रिप्लाइ दे देना (गोर एवं विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: आप उस मीटिंग में थे। मैंने 11 तारीख को रिप्लाइ देना है। (गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल: आप मैम्बरों को बाहर निकाल दें और फिर बोलने न दें, क्या यह ठीक है। (गोर एवं विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अगर ये गलत काम करेंगे तो यह स्पीकर का काम है कि उनको रखें या न रखे। (गोर एवं विधन)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी आपकी पार्टी पोजीशन के हिसाब से गवर्नर एड्रेस पर बोलने के लिए आप लोगों के 130 मिनट बनते थे जबकि आप लोग 132 मिनट बोल चुके हैं। आपके मैम्बर निकलने के बावजूद भी आप लोग गवर्नर एड्रेस पर पहले ही 132 मिनट बोल चुके हैं (गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल: जी नहीं, उनको गलत तरीके से हाउस से निकाला गया था। (गोर एवं विधन) पहले उनको आप बुलवायें, फिर ये रिप्लाइ दे लेंगे। (गोर एवं विधन)

आवाजें: नहीं, नहीं, नहीं। (गोर एवं विधन)

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं कैसे। यह तो रिकार्ड है। हमारे पास अलग-अलग समय है कौन कितनी देर बोला। (गोर एवं विधन) आपके जो मैम्बर थे उनको बोलने का पूरा समय दिया और सदन का समय भी बढ़ाया गया था। (गोर एवं विधन)

प्रो० सम्पत सिंह: इन्होंने बस्ते बांध लिए हैं, ये वाक आऊट करेंगे। (गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल: आपने गलत तरीके से उनको निकाला था। जो नाम हमने आपको दिए हुए हैं उनको आप बुलवायें। (गोर एवं विधन)

श्री अध्यक्ष: आपके जो मैम्बर थे, उन सभी बुलवाया गया था। (गोर एवं विधन)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, अब ये जायेंगे। (गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल: मंत्री जी क्या ये 7 मैम्बर बोलेंगे नहीं। (गोर एवं विधन)

प्रो० सम्पत सिंह: ये अपने बस्ते बांध रहे हैं, ये जायेंगे, ये वाक आऊट करेंगे। (गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल: ये सीनियर मैम्बर है, इनको आप बोलने दें। (गोर एवं विधन)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने बाहर जाने के लिए बस्ते बांध लिए हैं। (गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, ये 10-10 मिनट बोल लेंगे। ये 10-10 मिनट में अपनी बात कह लेंगे। (गोर एवं विधन) ऐसे कैसे बात बनेगी।

प्रो० सम्पत सिंह: आप भागेंगे।

चौधरी भजन लाल: नहीं, हम भागेंगे नहीं। हम यही रहेंगे। पहले आप हमारे साथियों को बोलने दीजिए। (गोर एवं विधन)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। कांग्रेस पार्टी के सदस्य पहले ही 132 मिनट बोल चुके हैं। जो सदन में थे हमने उन सबको बोलने का समय दिया। सदन चलता रहा लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी आदमी बोलने के लिए नहीं रह रहा था। (गोर एवं विधन)

आवाजें: हम तो आपको भी आगे बुलवाना चाहते थे लेकिन आप भी दौड़ गये थे। (गोर एवं विधन)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हमें आप बोलने का मौका दें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठे। (गोर एवं व्यवधान) आप भी चले गए थे। (गोर एवं व्यवधान) अभी बजट भी पे टा होना है और एप्रोप्रिये टान बिल भी आने हैं आप उन पर बोल लेना।

चौ० जय प्रका टा: अध्यक्ष महोदय, (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाए। (तोर एवं व्यवधान) जय प्रका 1 जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (तोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय,

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष: आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (तोर एवं व्यवधान) आप अखबार नीचे रखें, आप हाउस में अखबार नहीं दिखा सकते हैं। (तोर एवं व्यवधान) नो-नो आप अपनी अपनी सीटों पर बैठें। (तोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठें (तोर एवं व्यवधान) इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। कैप्टन साहब, मैं आपको वार्न करता हूं। जय प्रका 1 जी, आप भी अपनी सीट पर बैठें (तोर एवं व्यवधान) मैं आपको वार्न करता हूं। (तोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाईये। आपकी पार्टी के नेता ने बोलने के लिए जितने सरस्यों के नाम दिए थे वे सभी सदस्य बोल चुके हैं (तोर एवं व्यवधान) आप बैठें। हाउस का समय बढ़ाया गया था, जो समय बिजनैस ऐडवाजरी कमेटी की रिपोर्ट में निर्धारित हुआ था उसमें आपके 130 मिनट बनते थे लेकिन आपकी पार्टी के लोग 132 मिनट बोल चुके हैं इसलिए अब आप बैठें। (तोर एवं व्यवधान)

जो लोग बोल नहीं सके वे भी बोल सकते थे लेकिन आप लोग हाउस में रहे नहीं (गोर एवं व्यवधान)

आवाजें: हमें तो आपने नेम कर दिया था। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह मेरा कसूर नहीं था। (गोर एवं व्यवधान) यह मेरा कसूर नहीं था। जिसने गलती की उसको गलती की सजा मिल। (गोर एवं व्यवधान) चौधरी भजनलाल जी भी गलती का अहसास करते हैं। जो गलती करेगा उसको गलती का दण्ड तो मिलेगा ही। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जिन 7 मैम्बरों को आपने नेम कर दिया था उनको तो बोलने का मौका दें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजनलाल जी, आपके पीछे जो आपके मैम्बर खड़े हैं आप उनको तो बिठाए। (गोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आपकी बात कोई मानता तो है नहीं ये लोग तो आपको नेता ही नहीं मान रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान) आप अपने पीछे देखें कि क्या हो रहा है। (गोर एवं व्यवधान) आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें।

चौधरी भजन लाल: जो मैम्बर बोले नहीं और आपने उनको नेम कर दिया और हाउस से बाहर निकाल दिया आज वे अपनी बात तो कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: नो-नो आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। (तोर एवं व्यवधान) इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (तोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप यह बताएं आप इनको बोलने का मौका देंगे या नहीं देंगे?

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष: नो-नो आप बैठें। इतने लोगों में से मैं किस-किस की बात सुनूं। (तोर एवं व्यवधान) आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें। (तोर एवं व्यवधान) चौधरी भजन लाल जी, आप इनको कण्ट्रोल करें। (तोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप मैम्बर्ज को बोलने का मौका देंगे या नहीं देंगे। (तोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको बजट पर बोलने का मौका मिलेगा। (तोर एवं व्यवधान) इनकी कोई बात रिकार्ड न करें। (तोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाईये। (तोर एवं व्यवधान) क्या आप का यह कोई तरीका है? (तोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय,

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, ये सदन में थे।

श्री अध्यक्ष: मांगे राम जी झूठी गवाही नहीं दिया करते हैं। (तोर एवं व्यवधान) ये हाऊस में नहीं थे। आप राम किान फौजी से पूछ लें उस वकत चौधरी बंसी लाल जी की पार्टी सदन में थी। (तोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं। (तोर एवं व्यवधान) आप सब अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (तोर एवं व्यवधान) मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। (तोर एवं व्यवधान) चौधरी भजन लाल जी आप इनको अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहें। आप इनको सदन में बात करने की और बैठने की ट्रेनिंग दें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जिन मैम्बर्ज को आपने बोलने का मौका नहीं दिया है क्या आप उनको बोलने का मौका देंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी 7 तारीख को आपने जिन जिन मैम्बर्ज की लिस्ट दी थी उन सभी को बोलने का मौका दिया गया था। (तोर एवं व्यवधान) सभी पार्टीज को बोलने का मौका दिया गया है। अभी बजट भी पे 1 होना है उस पर भी आपकी पार्टी के मैम्बर्ज को बोलने का मौका दिया जाएगा। (तोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप हमारे मैम्बर्ज को राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर बोलने का मौका देंगे या नहीं। आप हमें हां या न में जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: आप पहले इन सबको बिठाएं।

चौधरी भजन लाल: ठीक है अध्यक्ष महोदय, हम सब अपनी सीटों पर बैठते हैं आप हमें यह बताएं कि हमारे मैम्बर्ज को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका देंगे या नहीं। आप हमें हां या न में जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे।

वाक्-आउट्स

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप हमारे उन सात मैम्बर्ज को राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर बोलने का मौका दे रहे हैं जिनको पिछले सप्ताह सदन से सस्पेंड कर दिया गया था इसलिए हम ऐज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक्-आउट करते हैं।

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी आपके मैम्बर्ज को पूरा टाईम दिया गया है, अब आप बैठ जाएं।

(इस समय सदन में उपस्थित इण्डियन नैशनल कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक्-आउट कर गए।)

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, आप सस्पेंडिड मैम्बर्ज को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो हम भी ऐज ऐ प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित हरियाणा विकास पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए।)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठ जाएं। लगता है कि आप भी उनकी तरह वाक-आउट करना चाहते हैं। अब सी0एम0 साहब ने रिप्लाइ देनी है इसलिए आप बैठ जाएं। लगता है आपमें अब अक्ल ठीक आयी है इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, आपने मेरी पार्टी को बोलने के लिए टाइम नहीं दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे गवर्नर ऐड्रेस पर अपनी बात कहने का मौका दीजिए। मेरे इलाके के लोगों की बात मुझे यहां पर कहने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी अपनी पार्टी की कोई कद्र ही नहीं करते। आप ही हाउस से वाक-आउट करके चले गए थे। कभी आप खुद चले जाते हैं और कभी आपका आचरण ऐसा होता है कि मुझे आपको हाऊस से निकालना पड़ता है। अब भी आपने

ऐसा ही आचरण भुरु कर रखा है। जब सबको बोलने का मौका दिया जा रहा था उस समय आप हाऊस में नहीं थे। आपकी पार्टी सात तारीख को हाऊस में नहीं थी।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, आप मुझे केवल पांच मिनट का बोलने के लिए समय दे दें। अगर आप मुझे बोलने के लिए समय दे देंगे तो मेरे इलाके के लोगों की समस्याएं भी यहां पर दर्ज हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: नहीं—नहीं, आप अब बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, जब आने कांग्रेस पार्टी को बोलने का समय दिया है, बी०जे०पी० को बोलने का समय दिया है, बंसीलाल जी की पार्टी को बोलने का समय दिया है और इंडीपेंडेण्ट्स को भी बोलने का समय दिया है तो मेरी पार्टी का भी हक है मेरा भी हक है कि आप मुझे बोलने के लिए समय दें।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, जो हाजिर हैं उनको ही बोलने का टाईम मिलेगा। पलवल में तो आपको बोलने के लिए टाईम नहीं दिया जाएगा। अब आने टोपी भी उतार ली है इसलिए अब आप बैठ जाएं। I warn you.

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, आपकी यह भी कोई बात है।

श्री अध्यक्ष: यही तो बात होती है। जब आपका व्यवहार ही ऐसा है तो यही बात होती है। अब जो भी दलाल साहब बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब,

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, अब आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है इसलिए अब आप बैठ जाएं। अब आप बगैर इजाजत के बोल रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब,

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, अब आप बैठें। अब आप हाऊस का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर आपका यहां से जाने का मन हो तो आप अपनी इच्छा पूरी करें। अन्यथा आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब,

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं। आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा। जो समय जिस चीज के लिए निर्धारित है उस समय पर वही मामला टेक-अप होगा। अब आप बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं कोई अन-पार्लियामेंट्री बात तो नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठें। जब समय आएगा तब आपको अपने इलाके के लोगों की बात कहने के लिए समय दिया जाएगा। अब आप वैसे ही हाउस का समय खराब कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाऊस का कितना कीमती समय है, कितना पैसा विधान सभा के संचालन में लगता है। कितने ऑफिसर्स यहां पर बैठे हैं लेकिन आपकी वजह से हाउस का सारे का सारा काम रूका हुआ है। आप इसमें विध्न डाल रहे हैं। आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, अगर आप मुझे बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं तो मैं इसके विरोध में सदन से वाक आउट करता हूँ।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के एक मात्र माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक-आउट कर गए।)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हम यह बात बार बार कह रहे हैं कि यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिस किस्म की भूमिका अपोजी उन के लोगों द्वारा यहां पर निभायी जा रही है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पीकर साहब, आपने अपने चैम्बर में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलायी थी और उस मीटिंग में विपक्ष के नेता भी उपस्थित थे और सदन के नेता भी उसमें उपस्थित थे। मुझे सारे हाउस को बताते हुए खुशी हो रही है कि

जब आपने यह मीटिंग बुलायी तो पहली बार उसमें युनानीमसली इस बारे में फैसला हुआ था वरना तो पहले यह होता था कि एक डायसैटिंग नोट विपक्ष के नेता ने भी यह माना कि गवर्नर ऐड्रेस पर डिसकान के लिए तीन फुल डे रखे जाएंगे और चौथे दिन मुख्यमंत्री जी का उस पर रिप्लाइ होगा। स्पीकर सर, अगर ये लोग सीरियस होते तो विधान सभा में पहले दिन से ही कंट्रीब्यूशन करते लेकिन इनका तो व्यवहार ही अच्छा नहीं था। आपने इनको स्वयं हाऊस से नहीं निकाला लेकिन जब इन्होंने हाऊस को चलने नहीं दिया तब मजबूर होकर आपने उनको हाऊस से निकाला। आपने तो उनको बार बार काल किया कि अगर उनमें से कोई भी बोलना चाहता है तो बोल लें लेकिन वे नहीं बोले। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि जब आपने उस दिन हाऊस का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया था तो विपक्ष के नेता ने कहा था नो नो! स्पीकर साहब, यह भी असैम्बली के इतिहास में पहली बार होगा कि रूलिंग पार्टी समय बढ़ा रही है और विपक्ष समय घटाने की बात कर रहा है। स्पीकर साहब, आपको याद होगा उस दिन भजन लाल जी ने और इनकी पार्टी ने नो-नो कहा था। अगर ये सीरियस होते तो ये टाइम बढ़ाने की बात करते। उस दिन पांच लोग गवर्नर ऐड्रेस पर पूरी तरह से बोले। हरियाणा विकास पार्टी के दोनों मैम्बर भी गवर्नर ऐड्रेस पर बोले। स्पीकर सर, मैं इस बारे में रिकार्ड की बात करके बताना चाहूंगा कि आपने उनको कितना टाइम बोलने के लिए अलॉट किया था। रूलिंग पार्टी को 300 मिनट का टाइम अलॉट किया था और वे

आपके सामने 150 मिनट बोले। केवल आधा समय हमारी पार्टी ने लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि विपक्ष के लोग ज्यादा बोलें। इंडियन ने जनल कांग्रेस को आपने 130 मिनट का टाईम दिया था और वे 132 मिनट बोले हैं और फिर भी आप हाउस को ऐक्सटैंड कर रहे थे लेकिन ये बोले कि हमें भूख लगी है हम जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र अपने पेट की भूख के लिए इनको प्रदे की भूख की परवाह नहीं है। केवल रोटी खाने के लिए पहले चले गए। स्पीकर साहब, हमारी सहयोगी पार्टी बी०जे०पी० को आपने 40 मिनट का टाईम दिया था और वे इतना बोले हैं, जिन तीन का नाम था वे पूरी तरह से बोले थे और बाकी मेंबरों से भी आपने बोलने के लिए पूछा था उसके बाद एच०वी०पी० के लिए 15 मिनट का टाईम रखा गया था और दिए गए टाईम से अधिक समय तक बोलने देने के बावजूद वे आज वाक-आउट करके गए हैं चौधरी बंसी लाल जी को वाक आउट करते समय थोड़ा बहुत तो महसूस करना चाहिए था उनको बोलने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया था और वे 40 मिनट बोले थे लगभग तीन गुणा समय दिया गया। यह भी कहा गया कि और समय लेना चाहें तो ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा फिर भी मैं याद कराना चाहता हूँ कि विपक्ष के नेता श्री भजन लाल जब बोलकर बैठ गए तो आपने भी इनको कहा था और मैंने भी कहा था कि बोलना चाहें तो और टाईम दे दें तो इन्होंने कहा था कि मैं बोल लिया मुझे इतना ही बोलना था। अध्यक्ष महोदय, आर०पी०आई., एन०सी०पी० और बी०एस०पी० के लिए दस-दस

मिनट का समय निर्धारित किया गया था इनके दो मेंबरों ने तो कंट्रीब्यूट किया नहीं था। मैं बी०एस०पी० के सदस्य को भाबा पी देना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के टोटल टाइम में से वे दस मिनट के स्थान पर बत्तीस मिनट बोले। इससे पता चलता है कि कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है? इंडिपेंडेंट्स के लिए 70 मिनट का समय निर्धारित था और वे 83 मिनट बोले हैं सबको पूरा टाइम मिला है। आज क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जवाब आना था। जवाब में सच्चाई और सच्चाई हमें कड़वी होती है और उसको ये साथी सुनना नहीं चाहते थे। जब बोलते हैं तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। आज हरियाणा प्रदेश में विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है उसकी वजह से केवल अखबारों में वाक-आउट का छप जाए इसलिए वाक-आउट कर गए हैं। इनका ये वाक-आउट बाकायदा निंदनीय है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

13.00 बजे

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सम्मानित सदस्यगण, हम पिछले चार दिनों से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने बड़ा भानदार और तथ्य से परिपूर्ण अभिभाषण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों को राज्य में हो रहे विकास के कामों की जानकारी मिली।

मैं पूरे सदन के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छा अभिभाषण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी एक बात कहता था और आज अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूँ, दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष बैठा नहीं है। असलियत यह है कि इस प्रदेश में सुदृढ़ विपक्ष है ही नहीं। स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रणाली में मजबूत विपक्ष का होना अति आवश्यक है लेकिन आज जो विपक्ष इस सदन में है उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। वह किसी मामले में सीरियस नहीं है। केवल मात्र अखबार की सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार के अनर्गल प्रचार करने में जुटे रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद पहला अधिवेशन जब भुरू हुआ तो विपक्ष सरकार के खिलाफ अधिवेशन वास प्रस्ताव लेकर आया, प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ और संख्या के आधार पर उस पर चर्चा भुरू हुई। अध्यक्ष महोदय, चर्चा भुरू होने से पहले सारा का सारा विपक्ष सदन के वाकआउट कर गया। अगली दफा फिर से अधिवेशन वास प्रस्ताव लेकर आये दूसरा अधिवेशन वास प्रस्ताव लाने में ये कितने सीरियस थे यह भी आप को मालूम है। इनकी पूरी संख्या ही नहीं थी सदस्यों की संख्या के अभाव में वह प्रस्ताव भी गिर गया। अध्यक्ष महोदय, आपने इस पद की गरिमा को कितने अच्छे ढंग से कायम रखा, यह मैं नहीं कह रहा बल्कि पूरे प्रदेश के लोग इस बात की सराहना करते हैं। एक पुरानी परम्परा जो आजादी मिलने के बाद से भुरू की गई थी। आप इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने के बाद

आपने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देकर नई परम्परा कायम की थी और एक विपक्ष अध्यक्ष के रूप में आपने पूरे सदन को बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित किया है। आपने किसी सदस्य को वार्निंग नहीं दी, किसी को नेम नहीं किया, किसी को निकाला नहीं बल्कि आपने तो बाकायदा विपक्ष के सदस्यों को बोलने के लिए कहा और विपक्षी सदस्य बाथ रूम में जाकर छिप जाया करते थे जैसा कि श्री सम्पत सिंह जी ने कहा आपने जब इनको बोलने का मौका दिया तो यह कह कर सदन से भाग जाते थे कि हमें तो भूख लग रही है। आप सदन का समय बढ़ाते रहे और वे सदन से भगते रहे। इससे ज्यादा अटपटी बात और क्या होगी। इतने कुछ करने के बावजूद भी उन्होंने पद की गरिमा का ध्यान न रखते हुए आपके खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव लेकर आये उसमें भी इनको रूलज रेगुले ांज का ज्ञान नहीं था। कानून कायदे पढ़े नहीं और उसका नतीजा यह निकला कि 14 दिन पहले जो नोटिस दिया जाना था वह नहीं दे पाये और उनका प्रस्ताव गिर गया अब की बार यमुनानगर की हार की छाप मिटाने के लिए भुरू से ही इन्होंने मर बनाया हुआ था कि अध्यक्ष के खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव लेकर आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये आपके खिलाफ अवि वास का प्रस्ताव लेकर आये। आपकी फिराखदिली की दाद देनी पड़ेगी कि आपने फौरन यह कहा कि जब सदन को मेरे अन्दर वि वास ही नहीं है तो मैं सबसे पहले सदन का वि वास मत अर्जित करके ही इस कुर्सी पर बैठूंगा। विपक्ष का प्रस्ताव आपने मंजूर करके उस पर चर्चा के लिए कहा तो उनके पास कहने

के लिए कुछ नहीं था और जो इस सदन का बेतकमीमती समय था, वह भी इन्होंने बर्बाद किया। आपके पद की गरिमा को बिगाड़ने की किस हद तक इन्होंने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, आपकी पेंस की दाद देनी पड़ेगी कि विपक्ष के सदस्य आपकी कुर्सी तक पहुंच गये आपकी भान में किस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किये, उनको दोहरते हुये हमें भार्म महसूस होती है। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने पीठ करके इस कुर्सी पर बैठकर अपने आप अध्यक्ष भी बन गये और एक-दूसरे मैम्बर के खिलाफ कानून की किताब फेंकते रहे। इस प्रकार का भद्दा प्रदर्शन प्रजातांत्रिक प्रणाली में भायद किसी सदन में नहीं हुआ होगा। इस देश की रियासत भी हैं और ईस्टर्न स्टेट भी हैं जहां अगर किसी को विरोध प्रकट करना हो तो वे लॉबी में जाकर विरोध लिख कर देते हैं। इस प्रकार की हरकत और कहीं नहीं होती। जिस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया और आपने फिर भी बहुत ही सब्र से काम लिया। खासतौर से एक कांग्रेस की महिला सदस्य ने तो सीट पर और बेंच पर समेत जूतों के बैठकर इस पूरे सदन की गरिमा को बर्बाद करने का काम किया। लेकिन चूंकि महिला सभ्यताविकरण वर्श था आपकी इस बात के लिए पूरा सदन प्रतिक्रिया करेगा कि आपने फिर भी उसके खिलाफ किसी प्रकार का ऐक्शन न लेने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, जोर भाोर से ये प्रचार किया करते थे यमुनानगर के उपचुनाव के बारे में बड़ा दुश्प्रचार फैलाया गया था। चुनाव का माहौल बिगाड़ने की बड़ी कोशिश की गई थी और यह चर्चा की जा रही थी कि अब इस

सरकार की उल्टी गिनती भुरू हो जायेगी। बहुत भाोर मचता था इस बात पर मुझे गालिब जी का एक भाोर याद आ रहा है

“बड़ी खबर गरम थी, गालिब के उड़ेगे परखचे,

देखने हम भी गये थे, पर तमा ना न हुआ”।

बहुत भाोर मचाया करते थे आखिर जाकर उनकी हालत यह हो गई कि सत्ता का ख्वाब लेने वाले लोग जो कहते थे कि सत्ता पक्ष की उल्टी गिनती भुरू हो जायेगी वे 21 से 20 होकर रह गये। गिनती उनकी उल्टी होनी भुरू हो गई क्योंकि उन्होंने भासनकाल में कुछ नहीं किया। यमुनानगर के उपचुनाव में जहां विकास के बहुत काम हो रहे थे वे पहले से ही तय हुआ थे जो विकास के काम थे वे ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत हो रहे थे फिर भी ये भाई चुनाव आयोग के समक्ष जाकर रोजाना इस बात की आपत्ति दर्ज कराते थे कि सरकार फलां जगह फलां काम करा रही है। अध्यक्ष महोदय, ये किसी मामले में भी सीरियस नहीं हैं। इनका बार बार अवि वास प्रस्ताव ले आना इनकी एक पुरानी आदत बन गई है और फिर ये वाक आउट दर्ज कराकर समाचार पत्रों की सुर्खियों में आने की कोशिश करते हैं इन्हें सरकार की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बहुत चिन्ता है। अध्यक्ष महोदय, जब हम विपक्ष में हुआ करते थे तो हम तो इस बात के लिए इंतजार किया करते थे कि हमें बोलने के लिए कुछ अवसर मिले, हम खुश हुआ करते थे। लेकिन आज जब सदन का अधिवेशन बुलाया जाता है

तो इनको बुखार आता है यह सोचकर कि अब सदन में जाना पड़ेगा, हम सदन में क्या कहेंगे, क्योंकि इनके पास कहने को कुछ ही नहीं। यही लोग जो इस बात के लिए आपत्ति किया करते थे कि क्वै चन आवर क्यों खत्म किया जाए। पिछली बार भी जब ये अवि वास प्रस्ताव लाए थे तो कह रहे थे कि क्वै चन आवर को समाप्त करके पहले अवि वास पर चर्चा की जाए और आज ये इस बात को भूल गए हैं और इसीलिए आज इनकी यह हालत हो गई है। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत जनहित के इतने काम किए हुए हैं कि पूरे के पूरे प्रदेश में किसी भी गांव में आज अगर जाया जाए तो जगह जगह पर विकास के कार्य होते दिखाई देंगे। सरकारें पहले भी थी लेकिन पहले काम नहीं होते थे और इसलिए काम नहीं होते थे क्योंकि जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई सत्ता में बने लोग डकार जाया करते थे और अब जब ऐसे लोगों जिन्होंने जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को दबाने का प्रयास किया है, के खिलाफ केस रजिस्टर्ड होते हैं तो इनको आपत्ति होती है और ये प्रैस के पास जाते हैं, कभी महामहिम राज्यपाल महोदय के पास जाकर कहते हैं कि बदले की भावनाओं के कारण हमारे खिलाफ केस दर्ज कराए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन के, इस स्टेट के पूरे ट्रस्टी हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रदेश की सम्पत्ति की देखभाल करें और लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सकें। इसलिए जनतांत्रिक प्रणाली को कायम रखते हुए 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत इस प्रदेश का बहुमुखी विकास करने का काम हमने किया

है। चौधरी बंसीलाल जी जो अब सदन में उपस्थित नहीं हैं एक बात कहते हुए हाउस से चले गए कि ये काम हमारे किए हुए हैं वे काम हमारे किए हुए हैं। बिजली के मामले में चौधरी बंसीलाल जी होते तो मैं उनको बताता, उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे वक्त में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी आंकड़ों में आपके और सदन के समक्ष रखना चाहूंगा कि चौधरी बंसीलाल के भासन काल में केवल मात्र 188 मेगावाट बिजली साढ़े 3 साल के अर्से में अधिक पैदा हुई। जब मैं विपक्ष में था तो इसी सदन में मैंने बंसीलाल जी को कहा था ओर हमने सदन में इसका पूरा विरोध किया था। इन्होंने पानीपत का दूसरे नम्बर का यूनिट 110 मेगावाट का चालू किया। अध्यक्ष महोदय, आप तो पानीपत जिले में रहते हैं, पानीपत का दूसरे नम्बर का यूनिट ए0बी0बी0 जर्मन कम्पनी के साथ साज बाज करके करोड़ों रुपये का उनको ठेका देकर कि इससे बिजली का उत्पादन बढ़ेगा उसको खुलवा दिया और आज साढ़े 4 साल हो गए हैं उस प्लांट की मीनरी खुले में पड़ी हैं। वहां 50-60 करोड़ रुपये का सामान पड़ा है और 300 करोड़ रुपये का हमारा उसमें नुकसान हो गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद हमने भी एक नम्बर की यूनिट खुलवाई और मैं पूरे सदन को बताना चाहूंगा और सदन इस बात को सुनकर प्रसन्न होगा कि एक नम्बर की यूनिट खोलकर उसको ठीक करने का काम किया गया है और उस पर मात्र 5-6 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। जहां इन्होंने 110 मेगावाट की दूसरी यूनिट का 100 करोड़ का ठेका ए0बी0बी0

कम्पनी को दिया था। वहीं हमने पानीपत की दूसरी युनिट को भी 5-6 करोड़ रुपये में ही ठीक करवाया है और उससे बिजली की क्षमता बढ़ी है। इन्होंने 300 करोड़ रुपये तो उस पर खर्चा कर दिया इसके अलावा जितना उत्पादन होना चाहिए था और जितना लाभ मिलना चाहिए था उससे भी पूरा प्रदे ा वंचित हो गया है। हमने अपने अढ़ाई साल के भासनकाल में 621 मेगावाट बिजली पैदा की है। बंसीलाल जी कहा करते थे कि मेरे वक्त में यह हुआ है, वह हुआ है। बंसीलाल जी हर मौके पर कहते हैं कि एस0वाई0एल0 नहर मैंने खुदवाई, इतनी बिजली मेरे वक्त में पैदा हुई। चौधरी जगननाथ जी, जो आज इस संसार में नहीं है, कहा करते थे कि तो गाम का पहाड़ भी तूने बनवाया, लाल किला भी तूने बनवाया। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद के पावर प्लांट से 143 मेगावाट बिजली हमारी सरकार के वक्त में तैयार हुई और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां 146 मेगावाट बिजली भी हमारी सरकार के वक्त में तैयार हुई। पानीपत की 210 मेगावाट की छठी यूनिट भी हमारी सरकार के वक्त में तैयार हुई। भाखड़ा की 15 मेगावाट और सलाल प्रोजैक्ट की 17.2 मेगावाट, टनकपुर कील 1.3 मेगावाट, चमेरा प्रोजैक्ट की 58.7 मेगावाट ऊंचाहार की 23 मेगावाट, राजस्थान अणु विद्युत केंद्र इकाई से 12.50 मेगावाट कुल मिलाकर 621.10 मेगावाट बिजली हमारी सरकार के वक्त में पैदा हुई है। अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि आज के दिन बिजली की बहुत जरूरत है। बिजली के बिना काम नहीं चल सकता। चाहे खेती हो, उद्योग हो, चाहे सार्वजनिक जीवन हो हर क्षेत्र में बिजली

की अति आवश्यकता है इसलिए हम बिजली के अधिक उत्पादन के लिए प्रयासरत हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने पानीपत की रिफाइनरी से भी बिजली का मामला तय किया है। चौधरी बंसी लाल जी अब यहां बैठे नहीं हैं उन्होंने भांका व्यक्त की थी कि पानीपत की रिफाइनरी से हमारा मामला तय हुआ है या नहीं? इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उनसे हमने 360 मेगावाट बिजली लेने का एग्रीमेंट किया है और इस बिजली के साथ साथ उनको हमने यह भी साफ साफ लिखा है कि वहां उनके साथ लगते इलाके को वे करोड़ों रुपये की सुविधाएं देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने पानीपत की 7वीं और 8वीं यूनिट्स जो 250-250 मेगावाट की हैं उनको भी 11वीं पांचसाला योजना में शामिल कर लिया है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कन्सलटेंट मुकर्रर हो गया और बड़ी तेजी से हम उस काम को भुरू करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी एक साथी कह रहे थे कि हम दो साल में बिजली पैदा कर देंगे। अब उनको ज्ञान तो है नहीं कि बिजली का चाहे हाईडल प्रोजैक्ट हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे गैस बेस्ड प्रोजैक्ट हो कम से कम 32 महीने का समय प्रोजैक्ट तैयार होने में लगता है। अध्यक्ष महोदय, हम बिजली की कमी को समझते हैं और इसलिए हम प्रयासरत हैं। हम तो यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट को भी जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हैं ताकि अधिक बिजली उत्पन्न हो। अध्यक्ष महोदय, गैस बेस्ड प्रोजैक्ट पर आधारित तीन संयन्त्र 500-500 मेगावाट के बारे में भी हमने केन्द्र से एम0ओ0यू0 साईन किया है और हम चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी तैयार हो जायें

तथा प्रदेशों को अधिक बिजली मिल जाये। अध्यक्ष महोदय, बिजली की दिक्कत को समझते हुए हम हमारी जितनी भी भुगर्भ मिलें हैं उनकी बगाज से और खोई से भी बिजली पैदा करना चाहते हैं ताकि सैंकड़ों मेगावाट बिजली उनसे भी पैदा हो सके और बिजली की कमी को पूरा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, हम एक तरफ तो बिजली का उत्पादन बढ़ाने में लगे हुए हैं दूसरी तरफ लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास बिजली की कमी होते हुए भी हमने दूसरे प्रदेशों से महंगे दामों में बिजली लेकर किसानों को सस्ते दामों पर दी है और इसका जीता-जागता सबूत है कि हमारा प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेसी साथी आज यहां हम बैठे नहीं हैं उनकी सरकार के वक्त में 20 या 25 लाख टन गेहूं केन्द्रीय पूल में जाता था और हमारे समय में 68 लाख टन गेहूं केन्द्रीय पूल में देकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पैदावार इसी वजह से बढ़ी है कि चाहे पानी हमारे पास थोड़ा है लेकिन हमने उस पानी को किसानों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की है, हमने अपनी नहरों की मरम्मत करवाई है। अध्यक्ष महोदय, हमने पंजाब की सरकार को भाखड़ा नहर की मरम्मत के लिए जिस बरतन में पूरा पानी नहीं पहुंचता था उसकी मरम्मत के लिए 12 करोड़ रुपया दिया लेकिन इन्होंने पैसा नहीं दिया इसलिए इनके समय में पानी कहां से आता? अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में जहां हमने बिजली बढ़ाने का प्रयास किया है वहीं हमारी सोच यह है और आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हमने आज

करोड़ों रुपये के बिजली के बकाया बिलों को लोगों से वसूल किया है। हमने लोगों को प्रेम से प्यार से समझाया है लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय में भजन लाल जी लोगों को गोलियों से मरवाते थे फिर भी ये एक पैसा वसूल नहीं कर पाये थे। अध्यक्ष महोदय, आज विपक्षी भाई लोगों में प्रचार करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं कि तुम बिजली का बिल अदा न करो। लोगों की सभाओं में जाकर लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं और लोग इनको अपनी सभाओं में आने नहीं दे रहे। अध्यक्ष महोदय, लोग यदि कहीं विरोध प्रदर्शन करते हैं और कांग्रेसी उसमें भागमिल होते हैं तो लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोगों को कांग्रेसियों से नफरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं लोगों को हमारे प्रति रोश हो सकता है लेकिन हम उस रोश को दूर करने के लिए किसानों को अनेकों प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। हमने लोगों को राहत दी है और लोगों को समझाकर राह—राज पर लाने का प्रयास किया है तथा लोग आज बकाया बिलजी के बिल अदा कर रहे हैं वहीं कुछ ऐसे अनसो ल एलिमेंट हैं जो उनको बहका कर उनको गलत रास्ते पर ले जा करके उनको गुमराह करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। हम लोगों को सुविधा प्राप्त करा सकते हैं लेकिन लोगों के हितों के साथ यदि कोई खिलवाड़ करके राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास करेगा तो हम उनके साथ सख्ती से निपटने में सक्षम हैं। हम जहां लोगों की इच्छाओं

को पूरा करने में सक्षम हैं वहां अगर कोई गलत काम करने की कोशिश करेगा तो हम उनसे भी निपटने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जहां पहले 2590 मेगावाट बिजली थी आज बढ़कर 3211 मेगावाट हो गई है। हम प्रदेश में और ज्यादा बिजली उत्पादन करने की कोशिश करेंगे। यहां पर कांग्रेसी पार्टी के लोग और चौधरी बंसी लाल जी और दूसरे लोग एक बात बार बार कहा करते हैं कि जब ये लोग विपक्ष में थे तो चौटाला रोज कहा करता था कि बिजली के बिल मत भरो। स्पीकर साहब, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम बिना पैसे के बिजली देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने तो अपने चुनाव घोशणा पत्र में जो 6 फरवरी, 2000 को मैंने रिलीज किया था उसमें यह साफ कह दिया था कि बिजली हम बिना पैसे के नहीं दे पायेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि हम पूरी बिजली दे। अध्यक्ष महोदय, 7 फरवरी, 2000 के अखबार में यह बात छप्पी हुई है। जो लोग यह कहते हैं कि हमारे द्वारा लोगों को बरगलाया जाता था कि बिजली के बिल मत दो। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी यहां पर बैठे नहीं हैं। अब वे यहां से उठ कर चले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब का एक ब्यान जो अखबार में छपा है, वे लोगों को क्या कहते हैं इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा। वे लोगों को कहते थे यानि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा कहते थे, इस बारे में उनका ब्यान 24 अगस्त, 2000 का है। वे कहते हैं कि चौधरी ओम

प्रका 1 चौटाला सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगातार झूठे वायदे कर रहे हैं और जब भी उन्हें लागू करने की बात आती है तो आचार संहिता को हथियार बना लिया जाता है। ये विचार आज जिले के कलिंगा गांव में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने व्यक्त किये। हुड्डा ने अपने ब्यान में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों को बिजली व पानी मुफ्त उपलब्ध करवाया जायेगा और साथ ही चुंगी माफ की जायेगी। जो लोग यह बात कहते थे, आज वे उस बात से मुनफिर होते हैं और उल्टा इल्जाम हमारे खिलाफ लगाते हैं जबकि हमारी सरकार का एक फैसला है कि हम लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के पक्षधर हैं। इसके अलावा हर स्तर पर केवल मात्र बिजली के मामले में नहीं बल्कि सिंचाई आदि के मामले में भी लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी हैं। हमने कितनी डिस्ट्रीब्यूटरीज और माईनर नये सिरे से चालू की हैं। जो माईनर आदि टूटी हुई थी या जो गलत बनी हुई थी उनको तोड़कर उनका लैवल ठीक किया है। हमने नहर के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। इस साल इतना भयानक सूखा होने के बावजूद भी हमने किसानों को पूरा पानी दिया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में आगे आने वाली गेहूं की फसल बम्पर क्रौप के रूप में होगी और बड़ी भारी मात्रा में होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को इस बात के लिए आ वस्त करना चाहूंगा कि आज किसान को बड़ी चिन्ता है कि सरकार गेहूं की फसल खरीदेगी या नहीं खरीदेगी क्योंकि अभी तक केन्द्र सरकार

ने गेहूं की सपोर्ट प्राइस भी मुकर्रर नहीं की है। इस बारे में हम भीघ्र ही केन्द्र सरकार से जा करके सम्पर्क करेंगे और किसानों का एक-एक दाना खरीदा जायेगा और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे।

अध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 का एक बड़ा अहं मुद्दा था। एस0वाई0एल0 नहर हरियाणा के लोगों के लिए एक जीवन रेखा है और खास करके दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए। अध्यक्ष महोदय, दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए जब इस नहर का पानी पहुंचेगा तो हमें 500 करोड़ रुपये प्रति साल का लाभ होगा और 4 लाख से अधिक एकड़ रकबा सहराब होगा। हमने इस नहर को बनवाने का निरंतर प्रयास किया है। एस0वाई0एल0 नहर बनवाने की भुरुआत चौधरी देवी लाल जी ने की थी। चौधरी देवी लाल जी ने ही सबसे पहले इसके लिए भूमि अधिग्रहण की थी। चौधरी देवी लाल जी ने पंजाब सरकार को 1 करोड़ रुपया दे करके इस पर काम भुरु करवाया था। ये लोग बार बार इल्जाम लगाते हैं कि बादल साहब के साथ इनकी दोस्ती है इसलिए एस0वाई0एल0 के मुद्दे को टरकाने का काम करते रहे। चौधरी देवी लाल के प्रयासों से ही नहर भुरु हुई थी। चौधरी देवी लाल जी ने ही इसकी भुरुआत की थी और पंजाब की सरकार ने जब इसके न बनाये जाने के लिए अड़चन डालने का काम किया तो चौधरी देवी लाल जी ही इसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ले करके गए थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चौधरी बंसी लाल जी

को बताया था और अब फिर वे मौके पर हैं नहीं। चौधरी बंसी लाल जी को विधान सभा में लाए गए अवि वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने सबसे पहले इस बात का विरोध किया था कि चौधरी देवी लाल जी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और वहां पर 10-12 साल उसका फैसला नहीं होगा और यह मामला लटक जाएगा जल्द से जल्द यह तैयार हो सकती थी। आज वे लोग कहते हैं कि यह हमारा प्रयास था जबकि कांग्रेस की सरकार में चौधरी बंसी लाल जी ने वह केस विदड़ा कर लिया था और 1982 में हम फिर से इस मामले को कोर्ट में ले कर गए थे। हमने इस केस की पूरी पैरवी की। आज हमारी उसी पैरवी का यह परिणाम है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला हमारे पक्ष में दिया। यह नहर हमारे प्रदेश की जो जीवन रेखा है वे लोग चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। मैंने विज साहब की कॉलिंग अटेंशन में भी इस बात को बताया था और मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूँ कि हर सूरत में नहर बनेगी और अब उसे कोई रोक नहीं पायेगा (इस वक्त मेजें थपथपाई गईं) पंजाब की सरकार को यह नहर बनानी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी एक बार यह बात कहीं थी कि जब कभी भी पंजाब में लोकप्रिय सरकार बनेगी उस सरकार को यह नहर बनानी पड़ेगी। क्योंकि यह सुप्रीमकोर्ट का फैसला है उसे कोई रोक नहीं सकेगा। हमें केन्द्र सरकार तक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। चौधरी बंसी लाल जी को पहले भी इस बात के लिए कहते थे और आज फिर हम कहते हैं कि नहर पहले टेल

पर से बनवा दी और उसका परिणाम यह निकला कि पंजाब में जो नहर बननी थी वह नहीं बन पाई जबकि हमारे एरिया में नहर बन गई। अगर उस वक्त चौधरी बंसी लाल जी ने इन्जीनियर इन चीफ श्री पाठक की बात मान ली होती तो हमारी यह नहर कभी की बन कर तैयार हो चुकी होती और हरियाणा आज दे 1 का नम्बर दो प्रदे 1 होने की बजाए नम्बर एक का खु 1हाल प्रदे 1 होता लेकिन इन लोगों की वजह से यह नहर नहीं बन पाई थी। अगर भुरु में उस वक्त यह नहर बना दी गई होती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी थी लेकिन केवलमात्र कमी 1न खाने के लिए टेल से नहर बनवा कर तैयार कर दी। अध्यक्ष महोदय, हैरानी इस बात की है कि जब हम यह कहते थे कि यह टेल से नहीं बननी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब एक साल के अन्दर अन्दर नहर बनेगी तो उसमें हमारी नहर की मुरम्मत करने में भी समय लगेगा उसमें हमारी डिस्ट्रीब्यूट्रीज और उनके आउटलैटस बनाने में भी समय लगेगा। हम एक मिनट का समय भी जाया करने के लिए तैयार नहीं हैं। ज्योंही हमें पानी मिलेगा त्यों ही पानी किसान के खेत की सिंचाई करेगा ताकि प्रदे 1 के किसान की पैदावार बढ़ सके। क्योंकि आज हमारे पास पानी की कमी है और जब तक हमें पूरा पानी नहीं मिलेगा तब तक पूरी पैदावार नहीं होगी इसलिए हम सारी ही तैयारी कर रहे हैं। दूसरे कामों को रोक कर भी हमें उसको पहले बनाना होगा क्योंकि उसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, एक खास मुद्दा और है जिस पर यहां पर चर्चा हुई। उस दिन मैं हाउस में नहीं था खासतौर पर

खनन ओर पहाड़ के मुद्दे को लेकर चौधरी बंसी लाल जी ने भी चर्चा की थी और दूसरे लोगों ने भी चर्चा की थी। अध्यक्ष महोदय, खान को ओपन ऑक्शन में लेने का निर्णय हमने किया। चौधरी बंसी लाल जी जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और इस सदन के सदस्य माननीय श्री करतार सिंह भडाना जी ने उस वक्त सुझाव दिया था कि उसका सबसे अच्छा हल यह है कि इन खानों की ओपन ऑक्शन कर दी जाए ताकि सरकार के खजाने में अधिक रैवेन्यू आ सके। लेकिन उस वक्त चौधरी बंसी लाल जी ने यह बात नहीं मानी। अध्यक्ष महोदय, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी पार्टी के सदस्य की बात को मानकर हमने ओपन ऑक्शन करने का निर्णय इसलिए लिया ताकि इससे हमारे खजाने में पैसा ज्यादा बढ़े। अध्यक्ष महोदय, जिस पहाड़ की खान का जिक्र किया गया है वह केवल मात्र 52 लाख रुपये में नीलाम होता था लेकिन अब सरकार को लगभग आठ करोड़ रुपये ओपन ऑक्शन में उसका मिला है। जो लोग उसका विरोध कर रहे थे उन लोगों ने भी उस की बोली दी हुई है। 6 करोड़ 51 लाख की बोली देने वाले उसका इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि यह केवल मात्र लाखों में जाया करती थी। अध्यक्ष महोदय, निगाना के पहाड़ का मैं जिक्र करना चाहूंगा। चौधरी बंसी लाल जी इस समय हाउस में बैठे नहीं है। चौधरी बंसी लाल के टाइम में वह पहाड़ 54 लाख रुपये में नीलाम हुआ था। कांग्रेस की सरकार के वक्त में नाके लगाने का काम हुआ था लेकिन आज ये लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं जबकि उन्होंने खुद भी नाके लगाने का काम

किया था उन्होंने विवाद किया था और ट्रैक्टर जलाए थे। तीन महीने तक ये लोग उस काम को चालू नहीं कर पाए थे आज खुद उन्होंने इस काम को चलाने का प्रयास किया आखिर उन्होंने इस काम को छोड़ने का काम किया। हमारी सरकार ने तो उस पहाड़ के ठेके दिए हैं जब कि उस पहाड़ की लूट का पैसा ये लोग खाया करते थे। उन लोगों ने जो उसी प्रकार से उसका विरोध करने का प्रयास किया तो हमने उन लोगों को समझा बुझा कर के सख्ती से उसको लागू करवा दिया। अध्यक्ष महोदय, कहां तो 54 लाख अया करता था। चौधरी बंसी लाल सदन से चले गए हैं वे बैठे होते तो मैं उनको बताता कि निगान पहाड़ का ठेका 10 सालतक उनके भाई रघुबीर सिंह के नाम पर था। इस ठेके का चौधरी रघुबीर सिंह के नाम पर बेनामी सौदा था। यह ठेका धर्मबीर एंड कम्पनी के नाम से उन्होंने लिया हुआ था। ई वर चंद गुप्ता और रघुबीर सिंह पुत्र मोहक सिंह हांसी रोड, भिवानी ठेकेदार के जमानती श्री बंसी लाल के भाई रहे हैं। 1-4-1992 से 31-3-1995 तक, 8-4-1995 से 3-3-1998 तक और 16-4-1998 से 31-3-1999 तक चौधरी बंसी लाल के भाई उनके जमानती रहे हैं। इस ठेके से केवल 40 हजार रुपये सरकार खजाने में जाते थे। एक अकेले पहाड़ के 40 हजार रुपये सरकारी खजाने में जाते थे। अब उस पहाड़ की ऑक्शन से 1.27 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उस पहाड़ में जो ठेका हुआ था उसमें क्या होता था, जो उस पहाड़ को तोड़ने वाले थे वे उस समय की सरकार को 24 रुपए प्रति टन के हिसाब

से रॉयल्टी दिया करते थे। लेकिन जो 20 प्रति टन सेल्ज टैक्स सरकार को देना होता था तो वे क्रै र वाले कोरा-मैटिरियल बिना पर्ची के दे दिया करते थे। बंसी लाल जी जो पर्चियां यहां दिखाया करते थे अगर वे सदन में होते तो मैं उनको बताता कि क्रै र वाले 20 प्रति टन सेल्ज टैक्स बचाने के लिए उनको लिखित रूप में यह लिखकर नहीं देते थे कि उन्होंने इतना रा-मैटिरियल लिया है। क्रै र वाले कच्चा पत्थर लेकर जो क्रै र बनाते थे उस पर जो 12 प्रति टन सेल्ज टैक्स लगता था वही सरकार के खजाने में जाया करता था। अध्यक्ष महोदय, हमने तो उनकी तरफ जो 80 लाख रुपया बकाया था वे भी वसूल किए हैं। यह वसूली हमने 12 दिसम्बर से लेकर बि तक की है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि 10 साल तक जिन्होंने उस पैसे को लूटा है, हम उनसे भी उस पैसे को वसूल करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रदेश को निरन्तर लूटते रहे थे उनके पास जहां पर पहले ठेका 52 से 54 लाख रुपए तक में जाया करता था अब वही ठेका 7 करोड़ रुपए से ज्यादा में नीलाम हुआ है। इसके बाद जो रॉयल्टी और सेल्स टैक्स आएगा वह लगभग 18 करोड़ रुपए हर साल आएगा। अध्यक्ष महोदय, कितना ही पैसा हर साल इससे सरकार का बढ़ा है। ये लोग जो यहां पर चिन्ता करते थे कि ओम प्रकाश चौटाला घौशणा मुख्यमंत्री है, घौशणा ही करता है विकास के काम कहां से होंगे? मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमने इस प्रकार के काम किए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने मार्किट फीस को 3 रुपए से घटा

कर 1 रुपया किया है लेकिन इसके बावजूद मार्किटिंग बोर्ड में काफी पैसा आया है। हमने व्यापारियों को अनेकों प्रकार की सुविधाएं दी हैं परन्तु उसके बावजूद भी हमारे पास काफी पैसा आया है। हमने दूसरे देाँ में जाकर के अपने देाँ के उद्योगपतियों से बातचीत की है उनको हरियाणा में आने का निमन्त्रण दिया है, उनसे सम्पर्क स्थापित किया है और उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं जिस वजह से हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार के उद्योग आए हैं जबकि इनकी सरकार के वक्त हरियाणा से उद्योग पलायन करने लग पड़े थे। हमारे वक्त में हरियाणा में नए उद्योग लगे हैं उनसे हमारे यहां पर उत्पादन बढ़ा है, व्यापारियों का व्यापार बढ़ा है और किसानों का उत्पादन बढ़ा है इस वजह से आज यह परिणाम निकल है कि हमारा रैवेन्यू 37 प्रति सैत इन्क्रीज तक चला गया है।। 37 प्रति सैत की इन्क्रीज की वजह से जो पैसा आया है वह जनता का पैसा है और हमने वह पैसा जनता पर ही खर्च करना शुरू कर दिया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार कहते थे कि मेवला महाराजपुर में पैसा खर्च नहीं हुआ है। उनको ज्ञान नहीं है कि मेवला महाराजपुर में मैं पहले चरण में गया था और वहां के लोगों से पूछ करके वहां पर विकास का काम किया गया था। अध्यक्ष महोदय, 5-6 विधान सभा क्षेत्र बाकी रह गए हैं दूसरे चरण में वहां पर भी जाएंगे। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हम तो भजन लाल और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के चुनाव क्षेत्रों में भी गए हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस वाल यहां पर नहीं हैं हम उन

सबके चुनाव क्षेत्रों में भी गए हैं। हरियाणा प्रदेश में अब पता नहीं मतदाता किस सोच में वोट दे देते हैं और वे अपनी सोच बदल भी सकते हैं। यमुनानगर का प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण सबके सामने हैं। हमने अच्छे काम किए हैं इसलिए लोग हमारे साथ हैं और हम लोगों के हितों के काम करते हैं। हमारी मंशा केवल एक ही है कि हम चौधरी देवी लाल जी के स्वप्नों को साकार करके हरियाणा प्रदेश को एक प्रगतिशील प्रदेश बना सकें और लोगों की मूलभूत जरूरियातें पूरी कर सकें। इसके लिए हमने हर क्षेत्र में काम किया है चाहे पशुधन को बढ़ावा देने की बात हो, हम यह मानकर चलते हैं कि आज खेती का जो मामला है उसकी वजह से किसान थोड़ा सा परेशान है क्योंकि गेहूं और चावल का इतना उत्पादन बढ़ गया है कि देश के गोदाम भरे पड़े हैं, सटे पड़े हैं और सबको इसकी चिंता हो रही है। केन्द्र सरकार भी चिंतित है कि इसको कैसे खपाया जाए? इसीलिए हमने केन्द्र की सरकार को सुझाया है और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारे सुझाव को मानकर फूड फोर वर्क स्कीम के तहत वह गेहूं हमें देना शुरू कर दिया है। अब इससे गांवों के विकास के कामों को और ज्यादा तेजी मिलेगी, गांव का विकास बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमने डायवर्सिफिकेशन की तरफ भी तवज्जो दी है और इसलिए हमने गन्ने की मिल लगायी हैं। चौधरी बंसीलाल जी चले गए। वे कहते हैं कि सिरसा की गन्ना मिल गन्ने के अभाव की वजह से बंद हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, सिरसा की भुगर मिल में पहले साल में ही सबसे ज्यादा गन्ना क्रय हुआ है और दस

परसैंट इसकी रिकवरी आयी है। पहली मर्तबा यह रिकवरी बढ़ी है। इनके वक्त में क्या हुआ है मेरे पास लिस्ट है अगर वे यहां पर होते तो मैं उनको बताता कि उनके वक्त में जो भुगर मिलें चली हैं उनमें पहले साल में किसी में एक लाख क्विंटल और किसी में 1.5 क्विंटल लाख गन्ना क्र 1 होता था लेकिन हमारी भुगर मिल ने पहले साल में 9 लाख क्विंटल से भी अधिक गन्ना क्र 1 किया है और दस परसैंट इसकी रिकवरी आयी है। अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले चौधरी भजनलाल जी मेरी गैर हाजिरी में कुछ कह रहे थे। सम्पत सिंह ने उनको इसके लिए डांटा भी, वे कहते हैं कि चार साल से गन्ने के दाम नहीं बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, उनको यह भी नहीं पता है। वे पिछले सै 11 में कभी तो कहते थे कि इंदिरा गांधी ने कहा था जबकि इंदिरा जी तो स्वर्ग में थी उसके बाद वे कहने लगे कि राजीव गांधी ने कहा जबकि राजीव गांधी जी उस दौरान नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, इनको ज्ञान ही नहीं है कि कौन कौन सी बात का यहां पर जिक्र किया जाए? मैं सदन का समय खराब करना नहीं चाहता। अगर ये लोग हाउस में होते तो मैं उनको कुछ बताता। हम चाहते हैं कि किसान ज्यादा गन्ना पैदा करें क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जो प्रकृति के प्रकोप को बर्दास्त कर सकती है। इसलिए गन्ना क्र 1 करने के लिए हमने दो भुगर मिलें लगायी हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर और अधिक गन्ना आएगा तो हम और भुगर मिल लगाएंगे। कृषि मंत्री भायद इसलिए ही देख रहे हैं कि हाथ के हाथ ही इस बारे में घोशणा कर दी जाए। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि गन्ना

किसान और ज्यादा पैदा करें। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी भुगर् मिलों ने किसानों के गन्ने के दाम साथ के साथ दे दिए हैं। इसमें कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं है। हमने तो कांग्रेस की सरकार के वक्त का जो गन्ने का बकाया था, वह पैसे भी दिए हैं और हिकसान को और ज्यादा पैसा देने का काम किया है। हम डायवर्सिफिके ान के हिसाब से जहां एक तरफ गन्ने की फसल को बढ़ावा देने जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ हम अन्य फसलों की तरफ भी ध्यान देने जा रहे हैं। इसीलिए हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर की अध्यक्षता में प्रगति िल किसानों का एक डेलीगे ान इजरायल भेजा था ताकि वह डेलीगे ान फ्लोरीकल्चर को देख सकें, सब्जी एवं फूलों की खेती को देख सकें और वहां की डेयरी को देख सकें। अध्यक्ष महोदय, हमने प ँ विकास बोर्ड का भी गठन किया है। किसान के जो दुधारू प ँ हैं हमने उनके लिए भी इनामा तय किए हैं। हमने 1500 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक किसान को दूध पैदा करने के लिए इनाम देना तय किया है। हमने तय किया है कि 12 लीटर तक दूध पैदा करने वाले किसान को इतना 12 से 15 लीटर तक दूध पैदा करने वाल किसान को इतना और 15 से 18 लीटर दूध पैदा करने वाल किसान को इतना इनाम दिया जाएगा। हमने किसान को आठ हजार रुपये तक दूध बढ़ाने के लिए दिए हैं ताकि वह प्रोत्साहित हो। इससे हमारी मुर्ा नस्ल भी कायम रहेगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एक बार हमारी केन्द्र की सरकार ने बाहर से आने वाले दूध पर एवं दूध के प्रोडक्ट्स पर

टैक्स नहीं लगाया था। मैंने उसी वक्त प्रधानमंत्री जी से इस बारे में जाकर कहा कि अगर आप बाहर से आने वाले दूध पर, दूध के प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर विदेशों का दूध और दूध से बनी हुई चीजें भारी मात्रा में यहां आएंगी और अगर ऐसा होगा तो इस प्रदेश का किसान आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने हमरी बात को मानकर बाहर से आने वाले दूध पर 60 परसेंट ड्यूटी लगा दी और उसका परिणाम यह निकला कि विदेशी दूध और दूध का बना सामान यहां पर नहीं आया। इसकी वजह से हमारे किसानों को बल मिला है। हम उनको इनाम देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसान की गाय, भैंस और बैल के लिए लाजिमी बीमा स्कीम के तहत आधा पैसा किसान देता है। इस तरह से हम किसान को पशुधन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम तो किसान के पशुओं की बीमारियों के लिए भी हिसार में एक सेंटर बहुत जल्द खोलने जा रहे हैं इस पर सैकड़ों करोड़ों रुपयों को खर्च आएगा। हम चाहते हैं कि हरियाणा डेयरी के मामले में, दूध के मामले में डेनमार्क जैसे मुल्क को भी मात दे सकें। हम इसके लिए प्रयासरत हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। हम पलोरीकल्चर को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऑयल सीड ज्यादा पैदा किया जाए। हम चाहते हैं कि पल्सेस ज्यादा पैदा की जाएं उसके लिए किसान को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अनेक प्रकार की सुविधाएं किसानों को देने के पक्षधर हैं। हमने किसान को, व्यापारी को और उद्योगपति को हर मामले में सहूलियतें दी हैं। अभी शिक्षा

के मामले को लेकर भी कुछ लोगों ने आपतियां की थी। हमने पहली जमात से अंग्रजी की शिक्षा शुरू की और छठी जमात से कंप्यूटर की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया है उस पर कुछ ने एतराज किया कि बिजली के बगैर कंप्यूटर शिक्षा कैसे चलाएंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि हमने कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए बाकायदगी से बिजली का पूरा प्रबंध किया है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम्पीटिशन में आगे बढ़ सकें और ग्रामीणोन्मुखी योजनायें बन सकें यह हमारा प्रयास है। हरियाणा प्रदेश के लोग विकास के कामों में आगे बढ़ सकें इसके लिए हम इन्फरमेसन टेक्नोलौजी को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने गुड़गांव में एक साइबर सीटी का फायनल कर दिया है और बहुत जल्द काम शुरू होने जा रहा है आज हरियाणा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर है और हम जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम पहले नंबर पर आएंगे। (विधन) हमने खेलों को भी बढ़ावा दिया है चौधरी बंसी लाल के भासन के दौरान भाराबबंदी के दौरान बच्चे दूसरी दिशा में मुड़ रहे थे जिनके बस्तों में किताबें होनी चाहिए थीं उनके बस्तों में किताबों के स्थान पर भाराब के पाउचिज हुआ करते थे। वे गलत बातों की तरफ तव्वजो दे रहे थे। हमने उनके अटेंशन को डायवर्ट कर दिया है और खेलों के क्षेत्र में अनेक प्रकार की सुविधायें प्रदान की हैं। हमने खिलाड़ियों को सर्विसेज में तीन परसेंट आरक्षण भी दिया है इसके साथी ही साथ खिलाड़ियों को दी जाने वाली खुराक की राशि 15 रुपये से बढ़ाकर तीस रुपये दी है इसके

अलावा बसों में मुफ्त सफर करने की अनुमति प्रदान की है। इस मौके पर मैं केन्द्र सरकार का भी आभार व्यक्त करूंगा कि चौधरी देवी लाल के नाम पर सोनीपत जिले में चौहान जो जी में चौधरी देवीलाल रीजनल सेंटर का काम भुरु कर दिया है। हमारा जो यूथ फ़ैस्टीवल 12 से 16 तारीख तक था ऐसा फ़ैस्टीवल इससे पहले भारतवर्ष में आज तक कहीं भी नहीं हो पाया था वहां उससे प्रभावित होकर केंद्रीय खेल मंत्री जी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोशणा कर दी है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) हम खेलों को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं हमने तो साहित्य और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया है। हम चाहते हैं कि कल्चर को बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारा पुराना जो आपसी प्रेम प्यार और भाईचारा है उसको मजबूत किया जा सके। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदे 1 हर क्षेत्र में प्रगति करें। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण प्रस्तुत किया है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान जिन सदस्यों ने जो रचनात्मक सुझाव दिए हैं मैं इस सदन को आ वस्त करना चाहूंगा कि उनके रचनात्मक सुझाव जो ठीक होंगे, उनको निश्चित रूप से माना जाएगा। हम जनतंत्र में वि वास रखने वाले लोग हैं हम चहुमुखी विकास के पक्षधर हैं जहां कहीं भी किसी भी सदस्य के क्षेत्र में विकास के कामों में दिक्कत आएगी वहां उनकी दिक्कतों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उनका समाधान किया जाएगा। अब मैं लॉ एण्ड ऑर्डर के बारे में बताना चाहूंगा। दूसरे प्रदे 1ों के मुकाबले में आज हरियाणा प्रदे 1 में ला एण्ड आर्डर सबसे ज्यादा अच्छा है। (विधन)

मुझे तो कांग्रेस के साथियों की ज्यादा चिंता है कभी ये किसी थाने में जाकर रपट दर्ज कराते हैं और कभी कहीं पर। (विधन) मुझे तो इस बात की भी चिंता है कि चौधरी भजन लाल कहीं आत्महत्या न कर ले इसके लिए हम सिक्कोरिटी का प्रबन्ध करना चाहते हैं। कभी ये कहते हैं कि छठे महीने सरकार गिरा दूंगा। हम जब विपक्ष में हुआ करते थे तब भी ये ऐसी वैसी ही बातें किया करते थे तब भी ये हमारे किसी मੈंबर को तोड़ नहीं पाए। अध्यक्ष महोदय, हम तो जनतंत्र में वि वास रखते हैं। हम जोड़ने वाले हैं तोड़ने वाले नहीं हैं। हम तोड़फोड़ की बात को बढ़ावा देने के पक्षधर नहीं है। मैं आपको वि वास दिलाना चाहूंगा कि हम जनतांत्रिक प्रणाली को बरकरार रखते हुए हरियाणा प्रदे 1 के आम नागरिक की मूलभूत जरूरतों को पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम चौधरी देवी लाल जी के स्वप्न को साकार करते हुए हरियाणा प्रदे 1 को पहले नंबर का प्रदे 1 बनाएंगे। अतः इसके लिए मैं आपसे और सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि गवर्नर महोदय के अभिभाषण को ज्यों का त्यों मंजूर करें, आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is-

That an Address be presented to the Governor in the following terms:-

“That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply stateful to the Governor

for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 4th March, 2002.”

The motion was carried.

वर्ष 2001–2002 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will present the Supplementary Estimates for the year 2001-2002.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates for the year 2001-2002.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker: Now, Shri Krishan Lal, Chairperson, Estimates Committee, will present the Report of the Committee on the Estimates on the Supplementary Estimates for the year 2001-2002.

Chairperson Estimates Committee (Shri Krishan Lal): Sir, I beg to present the Report of the Committee on the Estimates on the Supplementary Estimates for the year 2001-2002.

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: Now, the discussion and voting on the Supplementary Estimates will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, all the demands appearing on the order paper (No. 1 to 9, 11, 13 to 16 and 19 to 25) will be deemed to

have been read and moved together. Hon'ble members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand No. on which they wish to raise the discussion.

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,03,62,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 11,40,75,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 2-General Administration.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 51,01,35,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 14,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 3-Home.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 24,18,49000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 4-Revenue.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 7,24,92,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 5-Excise and Taxation.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 64,56,27,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 6-Finance.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 2,17,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 7-Other Administrative Services.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 8-Buildings and Roads.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 29,29,81,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 9-Education.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 6,74,62,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 11-Urban Development.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 8,01,8,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,19,50,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 5,51,14,93,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 14-Food and Supplies.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 15-Irrigation.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 300/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 16-Industries.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,29,47,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 19-Fisheries.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,65,47,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 20-Forest.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 82,98,91,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 21-Community Development.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,70,58,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 22-Cooperation.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 4,90,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 23-Transport.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs.1,50,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 24-Tourism.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs.85,23,77,,000/-** for revenue expenditure be granted to the

Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.**

(No member rose to speak)

Mr. Speaker: Now, I put the various demands to the vote of the House.

Mr. Speaker: Question is-

That the Supplementary sum not exceeding **Rs.1,03,62,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs.11,40,75,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 2-General Administration.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 51,01,35,000/-** for revenue expenditure and **Rs.14,00,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 3-House.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs.24,18,49,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 4-Revenue.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs.7,24,92,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 5-Excise and Taxation.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs.64,56,27,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 6-Finance.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 2,17,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 7-Other Administrative Services.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 1,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 8-Buildings and Roads.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 29,29,81,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 9-Education.**

Mr. Speaker: Question is-

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 6,74,62,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 11-Urban Development.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 8,01,8,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,19,50,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 5,51,14,93,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 14-Food and Supplies.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 15-Irrigation.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 300/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 16-Industries.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,29,47,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 19-Fisheries.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,65,47,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 20-Forest.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 82,98,91,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 21-Community Development.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 4,70,58,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 22-Cooperation.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs. 1,000/-** for revenue expenditure and **Rs. 4,90,00,000/-** for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 23-Transport.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs.1,50,00,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 24-Tourism.**

That the Supplementary sum not exceeding **Rs.85,23,77,,000/-** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 2002 in respect of **Demand No. 25-Loans and Advances by State Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till 11.00 a.m. on Wednesday, the 13th March, 2002.

***13.43 hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 11.00 a.m. on Wednesday, the 13th March, 2002.)